वर्ष : 17 ❖ अंक : 260 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

# अनुगामिनी

गंगटोक
शुक्रवार, 28 अप्रैल 2023

भारतीय बैकिंग प्रणाली मजबूत : शक्तिकांत दास 3

हताश कांग्रेस सत्ता पाने के लिए छटपटारही है : स्मृति ईरानी 6

## प्रमुख कार्यक्रमों में सीएम गोले को आमंत्रित किया जाना सिक्किम के लिए गर्व का बात : विकास बस्नेत

**अनुगामिनी का.सं.**

गंगटोक, 27 अप्रैल । सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने दिल्ली में आयोजित 'वन अर्थ, वन हेल्थ' की प्रतिष्ठित बैठक में भाग लिया। इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। देश भर से विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को इसमें आमंत्रित किया किया गया था। इस कार्यक्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना राज्य के लिए गर्व की बात है जो भारत के छोटे राज्यों में से एक है।

ये बातें मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव विकास बस्नेत ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह, ओडिशा में हॉकी विश्व कप के उद्घाटन समारोह जैसे प्रमुख समारोहों में सिक्किम की ओर से भाग लिया है। उन्होंने दावा किया कि सिक्किम सरकार के पास पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के शासनकाल के दौरान इस तरह से अग्रणी केंद्रीय कार्यक्रमों का समृद्ध इतिहास नहीं रहा है। राज्य में केंद्रीय मंत्रियों की आवाजाही बहुत कम होती थी, जहां केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों के आने से राज्य में अफरातफरी का माहौल बन जाता था और राज्य के सभी लोग सावधान हो जाते थे।

विकास बस्नेत ने कहा कि हालांकि वर्तमान में केंद्र के माननीय मंत्रियों का साप्ताहिक या मासिक आगमन जारी है। इससे राज्य को काफी लाभ हो रहा है और इससे यहां के आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विकास में भी मदद मिली है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सभी गतिविधियां मुख्यमंत्री श्री गोले के शिष्टाचार, अनुकरणीय नीति, विनय और विनम्रता के कारण है। केंद्र सरकार के साथ मधुर संबंधों के कारण पिछले महीने सिक्किम को जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर मिला। जिसमें देश विदेश की कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। राज्य के लोग मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि आज सिक्किम जैसे छोटे से राज्य को भी केंद्रीय कार्यक्रम के साथ-साथ मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित महान संबंधों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि विपक्ष के कुछ नेता लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री पर कई तरह के अपमानजनक आरोप लगाते आए हैं, लेकिन इन बातों की परवाह किए बिना मुख्यमंत्री केंद्र के साथ लगातार संबंध बनाए रखते हुए सिक्किम और यहां के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सिक्किम को दी गई मदद और समर्थन से राज्य का अस्तित्व और इसकी पहचान आज भी कायम है, और इस विश्वास के साथ कि मुख्यमंत्री की वही कुशल अवधारणा और केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध के कारण सिक्किम विकास और उपलब्धि की ओर आगे बढ़ेगा।

## आवास व शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने की बैठक

### विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा

**अनुगामिनी का.सं.**

गंगटोक, 27 अप्रैल । आवास तथा शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा आज स्थानीय एक होटल में एमओएचयूए, डीएफएस, यूडीडी, जीएससीडीएल, जीएमसी, एनएचबी, हुडको, एनबीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी और एसबीआई के प्रतिनिधियों के साथ दो अलग-अलग बैठकों का आयोजन किया गया।

समिति के सदस्य राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) की अध्यक्षता में हुई इन बैठकों में विभागों के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य शामिल हुए। वहीं इसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव वीबी पाठक ने किया। उनके साथ नगर विकास विभाग के सचिव एमटी शेरपा, विशेष यूडीडी सचिव श्रीमती रोशनी राई के अलावा सम्बंधित विभागीय अधिकारी भी थे।

इस अवसर पर पहली बैठक संसदीय स्थायी समिति और एमओएचयूए, डीएफएस, यूडीडी, जीएससीडीएल, जीएमसी, एनएचबी तथा एसबीआई अधिकारियों के बीच हुई। इसमें संसदीय समिति ने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, पीएमएवाई शहरी और पीएम स्वनिधि जैसी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

चर्चा में संबंधित मिशन निदेशकों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु जिम्मेदार प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट देखी गई। वहीं दूसरी बैठक संसदीय स्थायी समिति और यूडीडी, सीपीडब्ल्यूडी, जीएससीडीएल, जीएमसी, एनएचबी, एसबीआई, हुडको और एनबीसीसी के अधिकारियों के बीच हुई। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा संसदीय समिति को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट देखी गई।

बैठक में सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के लिए समिति के विभिन्न सुझावों पर भी विचार हुआ।

उल्लेखनीय है कि आवास व शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्य 27 से 30 अप्रैल तक राज्य के दौरे पर हैं। कल यह समिति नामची जाएगी।

## सीएम ने नई दिल्ली में इलाज करा रहे मरीजों से की मुलाकात

**अनुगामिनी का.सं.**

गंगटोक, 27 अप्रैल । प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने आज नई दिल्ली के दौरे पर प्रदेश के उपचाराधीन 55 मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

उन्होंने वहां मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान की और उनका इलाज कैसा चल रहा है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री गोले से मुलाकात के दौरान बीमार बच्चों ने मुस्कुराते चेहरों से आभार व्यक्त किया जैसे आज वे अपने माता-पिता से मिल रहे हों। मरीजों और उनके परिजनों ने उनके इलाज में नि:स्वार्थ देखभाल और सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री तमांग ने सरकार की ओर से हरसंभव सहायता प्रदान करने का वादा किया और मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) अपने दिल्ली दौरे से हमेशा वक्त निकालकर दिल्ली में इलाज करा रहे राज्य के मरीजों से मिलते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) का सपना है कि राज्य के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को भी सही समय पर इलाज मिले। इसी सपने को साकार करते हुए राज्य सरकार हर स्तर से मरीजों को प्रदेश और प्रदेश के बाहर इलाज के लिए भेज रही है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वयं सरकारी दौरे के दौरान मरीजों से मिलते हैं और यथासंभव उनकी मदद करते हैं। आज दिल्ली के सिक्किम हाउस में मरीजों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव शंकरदेव ढकाल, डीकेके भवन के चिकित्सा कर्मचारी उपस्थित थे।

## ऑपरेशन से पहले रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण : शेखर चतुर्वेदी

### घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

**अनुगामिनी का.सं.**

गंगटोक, 27 अप्रैल । सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भूमि राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर बेसिक एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षण शिविर का आज यहां संपन्न हो गया। इसमें भूमि राजस्व व आपूदा प्रबंधन सचिव सह राहत आयुक्त अनिल राज राई, एसएसडीएमए निदेशक प्रभाकर राई, अतिरिक्त सचिव श्रीमती परिना गुरुंग, अतिरिक्त निदेशक राजीव रोका, एनआईडीएम के सहायक प्रोफेसर शेखर चतुर्वेदी, एवं युवा पेशेवर अरुण वर्मा के अलावा अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

सत्र के दौरान सहायक एनआईडीएम प्रोफेसर शेखर चतुर्वेदी ने आपदाओं के दौरान नेतृत्व, संचालन, योजना एवं रसद आपूर्ति जैसे चार मुख्य कार्य क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए इसक उद्देश्यों, रणनीतियों, प्राथमिकताओं और घटना की अंतिम जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से स्थापित करने की बात कही। उन्होंने ऑपरेशन से पहले रणनीति विकसित करने को बहुत महत्वपूर्ण बताया। इसी तरह, उन्होंने घटना के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक संसाधन तथा सहायता प्राप्त करने के बारे में बोलते हुए कहा कि घटना संबंधी खर्चों पर नजर रखना, लेखा सूचना, खरीदारी, समयबद्धता और लागत विश्लेषण भी आवश्यक हैं।

वहीं एसएसडीएमए निदेशक प्रभाकर राई ने राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संगठन की जिम्मेदारियों पर प्रस्तुति देते हुए संगठन की भूमिका के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था, संसाधनों एवं उपकरणों को बनाए रखने के साथ-साथ आपात स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की राज्य की क्षमता के बारे में भी बताया। इसके तहत उन्होंने अस्पतालों एवं पीएचसी को जोडने के साथ आपात स्थिति के प्रबंधन हेतु कौशल विशेषज्ञों के साथ आबादी वाले क्षेत्रों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्ड में मानव संसाधन विकास पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर अपने समापन भाषण में सचिव सह राहत आयुक्त अनिल राज राई ने प्राकृतिक आपदा के नुकसानों को कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने लापरवाही को अधिकांश आपदाओं का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि इससे लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है और इनमें कमी लाने हेतु सतत विकास लक्ष्यों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और भविष्य के निर्माणों एवं सुविधाओं के भूकंप तथा भूस्खलन प्रतिरोधी होने की जरुरत बताई।

इससे पहले, श्री राई ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा, कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदा पर प्रतिक्रिया हेतु तैयारी के महत्व पर एक चर्चा सत्र भी हुआ। कार्यशाला में विभिन्न जिलों के डीएम, एडीएम, एसडीएम, राज्य सरकारी विभागों के नोडल अधिकारी के अलावा पुलिस, एसएसडीएमए, एसडीआरएफ, सेना के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

## राज्य में इनर लाइन परमिट लागू करना जरूरी : पेमा थुतेन सालाखा

**अनुगामिनी का.सं.**

गंगटोक, 27 अप्रैल । राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू करने की मांग को लेकर सुखिम मुलबासी सुरक्षा संगठन की कार्यकारिणी समिति की ओर से बुधवार को यहां राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव तथा आईएलपी समिति के सचिव छेवांग ग्याछो को एक ज्ञापन सौंपा गया।

सुखिम मुलबासी सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष एवं सलाहकार पेमा थुतेन सालाखा ने बताया कि राज्य में हाल के दिनों में हुई कई घटनाओं के मद्देनजर संगठन की ओर से यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि हम प्रशासन का ध्यान सिक्किम में आइएलपी के कार्यान्वयन के महत्व की ओर दिलाना चाहते हैं। हाल ही में हमारे राज्य में और इसके आसपास हत्या, बलात्कार, चोरी और अपहरण जैसी परेशान करने और दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई हैं। वहीं, जोरथांग में तो एक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर ले जाने का मामला भी सामने आया है। उनके अनुसार, ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें मीडिया में उजागर होने के बाद हम जानते हैं। लेकिन ऐसी कई अन्य घटनाएं भी होती हैं जिनसे हम अनजान रहते हैं। हर किसी में घटनाओं की शिकायत या एफआईआर दर्ज करने का साहस नहीं होता।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दुर्भाग्यजनक रूप से उपरोक्त मामलों के सभी अपराधी बाहरी लोग हैं जो बिना किसी उचित दस्तावेज के हमारे राज्य में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में राज्य में इनर लाइन परमिट का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वहीं सालाखा ने आइएलपी समिति गठित करने के लिए राज्य सरकार की सराहना भी की। उन्होंने कहा, हम एक संगठन के रूप में अपने लोगों की सुरक्षा और भलाई के बारे में चिंतित हैं। इसके अलावा, संगठन अध्यक्ष ने राज्य पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि हमारे पुलिस बलों ने सबसे हालिया मामले में अपराधी को खोजने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही उन्होंने पीड़ितों के प्रति न्याय की उम्मीद भी जतायी।

## राज्यस्तरीय पुस्तक मेले को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

**अनुगामिनी का.सं.**

गंगटोक, 27 अप्रैल । आगामी मई महीने में होने वाले राज्य स्तरीय पुस्तक मेले को लेकर आज यहां शिक्षा विभाग के सभागार में तैयारी एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य की संस्कृति सलाहकार श्रीमती भीम कुमारी शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राजनीतिक सचिव छिरिंग वांग्चुक लेप्चा, भाषा निदेशक सोनम लेप्चा, अतिरिक्त शिक्षा निदेशक चुकसुंग लेप्चा के अलावा संबद्ध विभागों के अधिकारी, चौदह भाषाओं के सभी साहित्यिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर सलाहकार श्रीमती शर्मा ने पुस्तक मेले को राज्य की जातीय भाषाओं को बढ़ावा देने एवं संस्कृति को परिभाषित करने वाला मंच होने के साथ ही प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा स्थानीय लेखकों और उनकी किताबों को बढ़ावा दिया है क्योंकि ये जातीय भाषा की किताबें हमारे सांस्कृतिक साहित्य के पहलुओं को सामने लाने में मदद करती हैं। इस कड़ी में उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी में सदस्यता 150 से बढ़कर 800 सदस्य होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मेले में विभिन्न भाषाओं के लिए स्टॉल लगाए जाने की भी जानकारी देते हुए राज्य में साहित्यिक गतिविधियों के प्रचार हेतु समर्थन के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के प्रति आभार व्यक्त किया।

वहीं बैठक में सीएम के एपीएस छिरिंग वांग्चुक लेप्चा ने छात्रों में पढ़ने की आदत डालने को पुस्तक मेले का मुख्य उद्देश्य बताते हुए इस वर्ष योक्सम में तृतीय 'रीड एंड ग्रो लिटरेरी फेस्ट' के भव्य आयोजन की जानकारी दी।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सिक्किम के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण योक्सम में आगामी 6 से 8 मई तक सिक्किम कला एवं साहित्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा जहां राज्य भर लेखकों और कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा।

इससे पहले, बैठक में एक खुली चर्चा आयोजित की गई जहां विभिन्न सुझाव दिये गये। वहीं संवाद सत्र के दौरान प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सिक्किम कला व साहित्य महोत्सव जयपुर के टीम आर्ट वर्क के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

## पीएम पोषण एवं मिड डे मील योजना पर कार्यशाला आयोजित

**अनुगामिनी नि.सं.**

नामची, 27 अप्रैल । जिले के विभिन्न सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, सेकेंडरी स्कूलों, जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों में पीएम पोषण एवं मिड डे मील योजना पर आज जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा नामची गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक स्कूल में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही पीएम पोषण एवं मिड डे मील योजना का सुचारू आयोजन सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर जिला पीएम पोषण, परीक्षा एवं छात्रवृत्ति निदेशक सोनम डेन्जोंगपा मुख्य अतिथि थे।

कार्यशाला को वक्ताओं के एक पैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें जिला स्वास्थ्य व परिवार कल्याण निदेशक डॉ. डीसी शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी के इम्बाराज, संयुक्त बागवानी निदेशक डुप छिरिंग काजी, संयुक्त जिला पीएम पोषण निदेशक श्रीमती पेमा ल्हामू भूटिया, जिला उप शिक्षा निदेशक श्रीमती एंजेला चिनगापा, डेस्मी उप निदेशक हरि प्रसाद राई एवं अन्य शामिल रहे।

इस दौरान, मिड डे मील के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान एवं छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागीय पहलों पर चर्चा की गई। वहीं इसमें छात्रों के लिए पौष्टिक आहार बनाए रखने के महत्व, बच्चों के लिए आधार कार्ड के महत्व, स्कूलों में जैविक उद्यानों की स्थापना और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण सहित बाल यौन शोषण से सुरक्षा आदि विषयों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा, कार्यक्रम में एक चर्चा सत्र भी हुआ जिसमें उक्त स्कूलों की प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

# मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ... हिमाचल दौरा रद्द करके सुनी थी खिलाड़ियों की बात : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के प्रदर्शन पर गुरूवार को कहा कि मैने अपना हिमाचल दौरा रद्द करके पहलवानों से बात की, उनकी हर बात सुनी और समिति बनाई गई जिसकी 14 बैठकें हुई। ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है और उसमें हमने कभी कोई समझौता ना पहले किया और ना ही आगे करेंगे।

ठाकुर ने कहा कि उन्हें निगरानी समिति के गठन से पहले विरोध कर रहे पहलवानों से बात की थी और उनकी मांग के अनुसार बबीता फोगाट को समिति में जगह भी दी गई थी। ठाकुर ने शिमला में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते हुए कहा, सरकार बहुत स्पष्ट है, मोदी सरकार सदा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। हम खिलाड़ियों के साथ खड़े थे, खिलाड़ियों को सुविधाएं दी और उन्हें बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल और खिलाड़ी प्राथमिकता हैं। उसके लिए हम कहीं पर भी कोई भी समझौता नहीं करते। ना आज तक किया है और ना आगे करेंगे।

खिलाड़ियों के विरोध पर खेल मंत्री ने कहा, जहां तक आप कुश्ती की बात करते हैं तो कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर-मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की। मैं हिमाचल प्रदेश का अपना पूरा दौरा रद्द करके 12 घंटे उनके साथ बैठा। सात घंटे एक दिन और साढ़े पांच घंटे अगले दिन। पूरी बातें सुनी। रात को दो-ढाई बजे प्रेस कांफ्रेंस हुई। उनसे पूछ कर समिति बनाई गई। उन्होंने कहा, शिकायत करने वाले समिति नहीं बनाते लेकिन सरकार को बनानी थी तो हमने बनाई। उन्होंने एक और व्यक्ति को शामिल करने को कहा। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया। हमने उसे भी शामिल किया क्योंकि हमारे मन में कुछ नहीं है। हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। निगरानी समिति बनाई गई। निगरानी समिति के सामने जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसे अवसर दिया गया। किसी पर कोई रोक नहीं थी। इनके कारण समय-सीमा भी बढ़ी थी। हमने समय-सीमा बढ़ाने का काम भी किया।

ठाकुर ने कहा कि निगरानी समिति की 14 बैठकें हुईं और किसी को भी सुनवाई के लिए आने से कभी नहीं रोका गया। उन्होंने कहा, समिति की 14 बैठकें हुई। जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है, वह आए। खिलाड़ी ने अगर किसी का नाम लिया और वह आना भी नहीं चाहता था तो हमने उसे भी आने की अनुमति दी। समिति की रिपोर्ट में जो कहा गया, उसके जो मुख्य निष्कर्ष थे कि निष्पक्ष चुनाव हों, तब तक कोई तदर्थ समिति बने, 45 दिन के भीतर चुनाव हों। आंतरिक शिकायत समिति बने, अगर किसी को मानसिक, यौन उत्पीड़न की शिकायत है तो महासंघ में उसके लिए समिति बने तो हमने उसके लिए भी कहा।

ठाकुर ने कहा, इसके साथ-साथ अगर कोई और समस्या है, जैसे टीम चयन है, टूर्नामेंट के लिए टीम भेजनी है तो हमने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ समिति बनाएगा और 45 दिन के भीतर चुनाव कराएगा, निष्पक्ष चुनाव होंगे और नई आम सभा आएगी, उसमें जो आंतरिक शिकायत समिति है वह उसमें काम कर सकती है।

खेल मंत्री ने पुलिस के पहवानाओं की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कहा कि कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करा सकता है लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। उन्होंने कहा, बाहर कोई भी कभी भी किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। अगर आठ साल पुराना मामला होगा तो प्राथमिकी आठ साल पहले भी हो सकती थी और आज भी हो सकती है लेकिन पुलिस भी शुरुआती जांच करती है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि हम शुरुआती जांच करेंगे और उसमें जो भी निकलता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे।

इसके इतर प्रदर्शनकारी पहलवानों पर बरसते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी टी उषा ने बृहस्पतिवार को कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। उषा ने आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा,पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है।

आईओए ने कुश्ती महासंघ के कामकाज के संचालन के लिये चुनाव होने तक एक तदर्थ समिति का गठन किया है जिसमें पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर, भारतीय वुशू संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश हैं जिनका नाम अभी तय नहीं हुआ है।

## कांग्रेस सत्ता में आई तो मछुआरों को 10 लाख का बीमा कवर देंगे : राहुल

बेंगलुरु, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कर्नाटक की सत्ता में उनकी पार्टी के आने पर मछुआरों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर देने का वादा किया। राहुल ने कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रति मछुआरा एक लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने, एक दिन में एक से लेकर 500 लीटर डीजल तक प्रतिलीटर 25 रुपये की सब्सिडी देने का वादा किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी में मछुआरा समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हम मछुआरों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर देंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस सरकार मछुआरों की जरूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील होगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके हितों की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, हम 5वीं गारंटी लागू करेंगे कि सभी महिलाएं सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलुरु में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 लाख का वादा किया था, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा किया था। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे सदन से निकाल दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि प्रधानमंत्री जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो पर कर्नाटक में जो हो रहा है उनको तो आप देखते नहीं।

## बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच करेगा

कोलकाता, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली जिले के कुछ हिस्सों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई झड़पों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया।

झड़पों के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की उसी खंडपीठ से संपर्क किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी की जांच की मांग की गई थी।

10 अप्रैल को, एनआईए अधिकारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट को भी सूचित किया कि अगर अदालत अनुमति देती है तो उन्हें इस मामले में जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है।

डिवीजन बेंच ने पाया कि यह राज्य पुलिस की क्षमता से परे है कि वह उन लोगों को ढूंढे जो झड़पों के लिए जिम्मेदार थे या जिन्होंने इसे उकसाया और इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच आवश्यक है।

न्यायमूर्ति शिवगणनम ने झड़पों के बाद अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इस तरह की झड़पों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटनाओं से लोग तनाव में रहते हैं।

इससे पहले, खंडपीठ ने अशांत क्षेत्रों में घरों की छतों से पथराव करने के संबंध में राज्य पुलिस की खुफिया शाखा की दक्षता पर सवाल उठाया था। खंडपीठ ने छतों पर पत्थरों के जमा होने की सूचना प्राप्त करने में खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाया।

## शाह और सरमा की मौजूदगी में उग्रवादी समूह ने किया शांति समझौते पर हसताक्षर

गुवाहाटी, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। उग्रवादी समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की मौजूदगी में सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शाह ने कहा कि राज्य में अब कोई आदिवासी उग्रवादी समूह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि असम के सभी आदिवासी उग्रवादी समूह अब मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, आज असम के सारे विवाद और हिंसा में लिप्त संगठन इस समझौते के साथ ही समाप्त होने जा रहे हैं। असम में अब एक भी आदिवासी समूह ऐसा नहीं है जो हथियार लेकर, कैंप लगाकर जंगलों में रहेगा। आज दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएससी) के साथ असम सरकार के समझौते के साथ ही सारे के सारे आदिवासी समूह आज मुख्यधारा में आ गए हैं। अपने क्षेत्र असम और भारत के विकास की प्रक्रिया में जुड़े हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी दोनों ने हिंसा खत्म करने और दिमासा के लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकमुक्त, हिंसामुक्त और विकासयुक्त पूर्वोत्तर की कल्पना देश के सामने रखी है। गृह मंत्रालय मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में हर रोज एक-एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है।'

शाह ने कहा, 'आज के इस ऐतिहासिक समझौते में सहमति बनी है कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के सभी प्रतिनिधि हिंसा का मार्ग छोड़कर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हिस्सेदार होंगे। सभी हथियार और गोला बारूद असम सरकार के सामने सरेंडर करेंगे। अपने सशस्त्र संगठन को

भंग करेंगे और कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली करेंगे। इसके तहत लगभग 168 से ज्यादा कैडर आज मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है।'

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए यात्रा में आसानी सुनिश्चित करने और इसके लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्री ने हवाई अड्डे के गेट, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच और आव्रजन क्षेत्र में व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए।

ताकि, यात्रियों को यहां अधिक समय न लगाना पड़े। एयरलाइंस को पीक सीजन के दौरान प्रतीक्षा समय के बारे में सोशल मीडिया पर रीयल-टाइम डाटा उपलब्ध कराने को कहा है।

## पीएम मोदी के मजाक पर भड़कीं प्रियंका गांधी, कहा- सुसाइड जैसे गंभीर विषयों का मजाक उड़ाना सही नहीं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुसाइड नोट पर किए मजाक को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी साझा किया है, जहां वह एक चुटकुला सुना रहे हैं, जिसमें एक युवती अपने प्रोफसर पिता के नाम चिट्ठी छोड़ जाती है कि वह आत्महत्या करने जा रही है।

उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि युवाओं में अवसाद और आत्महत्या जैसा विषय हंसने वाली बात नहीं है। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो पीएम के चुटकुले पर ठहाके लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के असंवेदनशील लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का उपहास करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूक करना चाहिए।

उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2021 में एक लाख 64 हजार 33 भारतीयों ने आत्महत्या की है। इसमें से एक बड़ा प्रतिशत 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों का था।

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम पर वार किया। उन्होंने कहा कि हजारों परिवार अपने बच्चों को आत्महत्या के कारण खो देते हैं उन्हें इस बात को लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होते हुए हल्के-फुल्के मूड में जोक सुनाया था। उन्होंने बताया कि यह चुटकुला हम बचपन से सुनते आए हैं। एक प्रोफसर थे। उनकी बेटी ने आत्महत्या की, जो एक पत्र छोड़कर गई कि मैं जिंदगी से थक गई हूं। मैं जीना नहीं चाहती हूं, मैं कांकरिया में कूद कर मर जाउंगी। सुबह प्रोफसर ने देखा कि बेटी घर में नहीं है। ढूंढने पर उसके बिस्तर पर एक चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर प्रोफसर को गुस्सा आया।

वह सोचने लगे कि मैं प्रोफसर... मैंने इतने साल मेहनत की और मेरी लड़की अभी भी कांकरिया की स्पेलिग गलत लिख रही है। पीएम के इस चुटीले अंदाज पर जहां लोग ठहाके भरते नजर आए तो वहीं प्रियंका गांधी ने आत्महत्या जैसे गंभीर विषय पर चुटकुले सुनाने पर हैरानी जताई है।

## 'जबरन काम शुरू नहीं होगा, ना अन्याय होने देंगे', बारसू रिफाइनरी विवाद पर बोले सीएम शिंदे

मुंबई, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। महाराष्ट्र में बारसू रिफाइनरी को लेकर विवाद चल रहा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह जबरन बारसू रिफाइनरी का काम शुरू नहीं करेंगे और ना ही लोगों के साथ अन्याय होने देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में बारसू रिफाइनरी स्थापित की जा रही है लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हजारों करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी पार्टियां राजनीति के तहत इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं।

बता दें कि रत्नागिरि जिले के राजापुर तहसील के बारसू में पेट्रोकेमिकल का ख्लांट स्थापित किया जाना है। इसके तहत एक मेगा रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाना है लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्लांट के निर्माण से क्षेत्र की जैव विविधता तबाह हो जाएगी। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

अब विरोध के बीच गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी भी हालात में महाराष्ट्र सरकार लोगों के साथ अन्याय करके या जबरन या लोगों की मर्जी के बिना बारसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगी। उन्होंने मुंबई नागपुर के समृद्धि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया और बताया कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का भी विरोध हुआ था। शिंदे ने कहा कि सभी पक्षों को विश्वास में लेकर ही कोई कदम उठाया जाएगा। सीएम ने कहा कि कई लोग अभी भी प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट साइट पर बोरिंग और मिट्टी की जांच चल रही है लेकिन तुरंत बारसू प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो रहा।

## सीएम शिंदे ने किया राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन, आरएसएस प्रमुख को बताया प्रेरणा का स्रोत

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। उन्होंने भागवत को अपने और दूसरों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्त्रोत बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस प्रमुख लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए सहायता भा करते हैं।

इस कार्यक्रम में मोहन भागवतत के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्योगपति गौतम अदाणी भी मौजूद थे। इस सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा- 'मोहन भागवत हम सभी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्त्रोत हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं भागवत उनकी सहायता करते हैं।'

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान आरएसएस के विचारक डॉ आबाजी थट्टे की भी सराहना की।

उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने भागवत की सराहना करते हुए कहा- संघ राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के निर्माण में एक प्रेरणा के रूप में खड़ा था। आरएसएस के समर्थन से ही भव्य

परियोजनाओं का निर्माण संभव हो पाता है।

उन्होंने कहा- हेल्थ केयर प्रणाली और कैंसर सभी के लिए एक चुनौती है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर साल 1.25 लाख मरीज कैंसर के शिकार हो रहे हैं, जिसमें से 30 से 40 फीसदी लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गवां रहे हैं। मरीजों को गुणवत्ता कैंसर उपचार देना एक बड़ी चुनौती है और सरकार इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

ठाणे में कोपरी-पचपखड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एकनाथ शिंदे ने थाणे में भी कैंसर अस्पताल खोलने का दावा किया।

इस सभा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को बनाने में संघ की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान फडणवीस के दिमाग की उपज हैं, जो आरएसएस के ही सदस्य है। अपने पहले चरण में संस्थान ने 2017 से मरीजों को सेवाएं देना शुरू किया था।

फडणवीस ने बताया कि उनके पिता की मौत भी कैंसर की वजह से ही हुई थी। एक कैंसर मरीज और उनके परिवारवालों को कितनी परेशानी होती है इसे वह अच्छी तरह समझते हैं।

मोहन भागवत ने लोगों को एकजूट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा- 'शिक्षा और उपचार हमारे समाज की बुनियादी जरूरते हैं। सभी को एक अच्छी शिक्षा और उपचार चाहिए, जिसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार और प्रशासन काम कर रही है। इसके लिए 148 करोड़ लोगों का भी साथ चाहिए।'

नितिन गडकरी ने इस अवर पर कहा कि अमेरिका में हर साल कैंसर मरीजों की संख्या में 33 फीसदी की वृद्धि होती है। लेकिन इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भारत में ज्यादा है।

उन्होंने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान पर उम्मीद जताते हुए बताया कि ये हमारे समाज में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केंद्रीय मंत्री नागपुर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने देश को इस बीमारी से मुक्त बनाने के लिए कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

# 32 हजार करोड़ की योजनाओं से लौटेगा ब्रज का वैभव : योगी

मथुरा, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। मथुरा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। धर्म नगरी मथुरा में ही 32 हजार करोड़ की योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनके पूरा होते ही ब्रज का द्वापरकालीन वैभव लौट आएगा। यहां की जनता का आशीर्वाद मिला तो काशी विश्वनाथ धाम के पैटर्न पर बांकेबिहारी का भी भव्य धाम बनेगा। अयोध्या की भांति ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा पर जल्द काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के खेल मैदान में भाजपा के मेयर व अध्यक्ष प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले इसी मथुरा में जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी। खूब खून खराबा हुआ था। आज वही जवाहर बाग एक बेहतरीन पार्क है। 2017 से पहले ही कोसीकलां में भी दंगा होता था, आज वहां औद्योगिक इकाइयां लग रहीं हैं और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले मथुरा-वृंदावन और गोकुल में मांस और मदिरा बिकती थी। हमने कहा दूध, दही वाले क्षेत्र की पवित्रता के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसी भावना के तहत मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव आदि सभी पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित कर वहां बड़ी कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि अब चौरासी कोस की परिक्रमा केवल अयोध्या धाम में ही नहीं होगी, ब्रज धाम में भी होगी। इसके लिए सांसद हेमामालिनी के नेतृत्व में यहां के जनप्रतिनिधियों ने भारत सरकार के साथ समन्वय कर कार्ययोजना को अंजाम दिया है,जो बहुत जल्द ही धरातल पर नजर आएगी। सीएम ने कहा ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। ये जब पूरी होंगी तब ब्रज में द्वापर युग यादों को ताजा कराएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, मथुरा-वृंदावन नगर निगम बनने के बाद यहां बड़ा परिवर्तन आया है। आजादी के बाद विभिन्न सरकारों में जिस प्रकार की लचर, भ्रष्टाचार से युक्त और अराजकता पूर्ण व्यवस्थाएं थीं उस कचरे की सफाई करने में समय तो लगता है। मुकेश आर्य बंधु यहां के पहले मेयर हुए और उन्होंने बदलाव की जो शुरुआत की थी उसे आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ धाम बन गया, इसी प्रकार यहां बांकेबिहारी का धाम भी बनेगा। बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है। उसे भी भव्यता देनी है। गोकुल में रसखान की समाधि को नया स्वरूप दिया है। गोवर्धन को द्वापरकालीन प्राचीनता देनी है। इसके लिए सभी मिलकर काम करेंगे तो कृष्ण कन्हैया, राधारानी की भूमि और यमुना महारानी के वैभव को लौटाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने नगर निगम में महापौर पद के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल सहित अन्य सभी निकायों के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इससे पूर्व सांसद हेमामालिनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह शाक्य, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह सहित विधायक पूरन प्रकाश, राजेश चौधरी, ठाकुर मेघश्याम सिंह, एमएलसी ठाकुर ओमप्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के चेयरमैन तेजवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह, रविकांत गर्ग, देवेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। संचालन महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी ने किया।

# कर्नाटक के बीजेपी कार्यकताओं को पीएम मोदी ने किया संबोधित, दिए कमल खिलाने के गुरुमंत्र

**राजेश अलख**

नई दिल्ली, 27 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि डबल इंजन की सरकार होने का सीधा मतलब राज्यों में विकास की दोगुनी रफ्तार से है और इसके ना होने से जनता पर डबल मार पड़ती है।

चुनावी राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं से डिजिटल माध्यम से संवाद करते हुए मोदी ने आग्रह किया कि वे जनता के बीच जाएं और बताएं कि डबल इंजन सरकार के क्या फायदे हैं।

केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने को भाजपा डबल इंजन की सरकार कहती है। हाल के वर्षों में विधानसभा चुनावों में पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है।

पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता को समझाएं कि स्थिर सरकार होने के फायदे होते हैं। उन्होंने कहा, मतदाताओं को बताएं कि कर्नाटक में स्थिरता ना होने की वजह से कितना नुकसान हुआ है और दिल्ली में (केंद्र में) एक स्थिर सरकार होने की वजह से कितना काम हो रहा है। इस बार यहां भी मजबूत और स्थिर सरकार बनाइए।

मोदी ने कहा, डबल इंजन सरकार का सीधा और साधारण मतलब है कि विकास की रफ्तार डबल। बीते नौ वर्षों का यही अनुभव रहा है। जहां-जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां-वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी हैं।

उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना में कर्नाटक सबसे आगे है और यह इसलिए संभव हुआ है कि क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, वहां वह (सत्ताधारी दल) कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना सफल न हो जबकि कुछ राज्य तो योजना से जुड़ते ही नहीं हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो योजना का नाम तक बदल देते हैं।

उन्होंने कहा, अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात-बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी अवसंरचना से जुड़ी सारी परियोजनाओं को अटकाती रहेगी हम सड़कें बनाना चाहेंगे तो जमीन का काम ही धीरे-धीरे करेंगे तो कैसे निवेश आएगा? निवेश नहीं आएगा तो कर्नाटक में नए रोजगार कैसे सृजित हो पाएंगे? यानी डबल इंजन की सरकार के ना रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती है।

प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ट्रैक्टर के एक पहिये की जगह उसमें मारुति कार का पहिया लगा दें तो वह क्या किसी के काम आएगा? उन्होंने कहा, क्या वह खुद ही अपनी बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था तेज गति देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार तेज गति देती है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जाकर मतदाताओं को इसके फायदे बताएं।

प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 50 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक में विधान सभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बूथ जीतने पर फोकस करने की सलाह दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, बूथ जीतने की शुरूआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। उन्होंने कहा कि यदि आप बूथ स्तर पर जीतना चाहते हैं तो 10 महिलाओं और 10 पुरुषों का एक मजबूत समूह बनाएं। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और दलितों के कल्याण सहित सरकार की योजनाओं की जानकारी रखें और पूरी तरह से स्वयं को अपडेट रखते हुए इन जानकारियों को जनता तक पहुंचाएं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह दो दिन बाद कर्नाटक की जनता का दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। राज्य में प्रचार करने वाले नेताओं ने उन्हें बताया है कि उन्हें वहां के लोगों का भरपूर स्नेह मिला है। यह भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास को दिखाता है।

विरोधी दलों पर सीधा निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि विरोधियों का एजेंडा सिर्फ सत्ता हथियाना है जबकि भाजपा का एजेंडा विकास है। उन्होंने कहा कि, भाजपा और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। भाजपा आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना और हमारा एजेंडा है 25 वर्षों में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना और युवाओं के सामथ्र्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए भाजपा एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। उन्होने कहा हमारी कोशिश है कि कर्नाटक में बेंगलुरु जैसे अनेक वैश्विक केंद्र बनें।

मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एकमात्र एजेंडा सत्ता हथियाना है।

प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर निशाना जारी रखते हुए आगे कहा कि, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम, दाम, दंड, भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाले पीढ़ियों की, कनार्टक के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य अपनी दलगत भलाई के लिए बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। राज्य डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी ये खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती।

उन्होंने कहा कि जब भाजपा को सेवा को मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाती है। 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे, हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन रहे हैं। पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70-75 हजार रुपये की मदद दी जाती थी, आज ये मदद 1 लाख 30 हजार रुपये कर दी गई है। इससे भी बड़ी बात ये है कि अब पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं, कोई बिचौलिया नहीं होता है।

प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पहली बार के मतदाताओं से जरूर मिलें और उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने कहा, लंबे अरसे से कर्नाटक में भाजपा का बड़ा जनाधार रहा है। आप पूर्ण बहुमत की स्थिर भाजपा सरकार के लिए वोट मांगेंगे तो जनता जरूर आशीर्वाद देगी।

कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है और मतगणना 13 मई को होनी है।

# भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत : शक्तिकांत दास

मुंबई, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश की बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी हुई है और वैश्विक घटनाक्रमों का इसपर खास प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है।

दास ने अमेरिका में हाल की घटनाओं के लिए खराब कारोबारी मॉडल को भी एक वजह बताते हुए कहा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी हुई है और वैश्विक घटनाक्रमों का इसपर खास प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है।

उनका यह बयान सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के कुछ सप्ताह बाद आया है। इस घटनाक्रम से अमेरिका और यूरोप के वित्तीय क्षेत्र में संकट की स्थिति पैदा हो गई है।

दास ने कहा कि अमेरिका के हाल के घटनाक्रमों से यह सवाल खड़ा हुआ है कि क्या व्यक्तिगत बैंकों का कारोबारी मॉडल सही था।

रिजर्व बैंक प्रवर्तित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा वित्तीय क्षेत्र की मजबूती पर एक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा, भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई और कुछ आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय अस्थिरता का इसपर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है।

उन्होंने कहा, रिजर्व बैंक ने अब बैंकों के कारोबारी मॉडल पर नजदीकी निगाह रखनी शुरू की है। इनमें किसी तरह की खामी से संकट पैदा हो सकता है।

दास ने कहा कि कारोबारी मॉडल कई बार बैंक के बही-खाते के कुछ हिस्सों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, जो बाद में एक बड़ा संकट बन सकता है।

दास ने कहा, रिजर्व बैंक के दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि अत्यंत संकट वाली स्थिति में भी भारतीय बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात को न्यूनतम जरूरत से ऊपर रखने में सफल रहेंगे।

उन्होंने बैंकों के प्रबंधन और निदेशक मंडल से नियमित रूप से वित्तीय जोखिम का आकलन करें और पर्याप्त पूंजी और तरलता बफर बनाने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंकों की लगातार मजबूती और सतत वृद्धि के लिए यह न्यूनतम नियामकीय जरूरत से अधिक होना चाहिए।

गवर्नर ने अंशधारकों को सतर्क करते हुए कहा कि दुनियाभर में परंपरा से हटकर नीतियां अपनाई जा रही हैं। ऐसे में वित्तीय क्षेत्र में किसी तरह का आश्चर्य कहीं से भी देखने को मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक भविष्य के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और इसकी सतत वृद्धि को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

गवर्नर ने कहा कि भारतीय बैंकों ने हाल के समय में दबाव और पूंजी बफर के मोर्चे पर सुधार दर्ज किया है। बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां अनुपात दिसंबर, 2022 में घटकर 4.41 प्रतिशत रह गया है, जो मार्च, 2022 में 5.8 प्रतिशत और 31 मार्च, 2021 को 7.3 प्रतिशत था।


**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली**

**नर्सिंग आफिसर भर्ती कॉमन पात्रता टेस्ट (एनओआरसीईटी) 4**
**सूचना सं. 76/2023 दिनांक 12.04.2023**
**www.aiimsexams.ac.in**

एआईआईएमएस नई दिल्ली एवं क्रमिक संस्थानों में अन्य एआईआईएमएस को उपलब्ध रिक्तियों के लिए नर्सिंग ऑफिसर पदों पर लेवल 07 में पे मैट्रिक्स प्री-रिवाइज्ड पे बैंड- 2 ₹ 9300-34800, ₹ 4600/- के ग्रेड पे के साथ ग्रुप बी की भर्ती के लिए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन पात्रता टेस्ट (एनओआरसीईटी) के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

**ऑनलाईन आवेदनों को एआईआईएमएस वेबसाईट www.aiimsexams.ac.in के माध्यम से 12.04.2023 से 05.05.2023 को 5.00 पीएम तक आवेदन किया जा सकता है।**

**एनओआरसीईटी में उपस्थिति के लिए पात्रता-मापदंड:**

**आवश्यक योग्यता**

I
- **अ.** बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग/बी.एससी नर्सिंग, भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से
  **अथवा**
  **बी.एससी** (पोस्ट-सर्टिफिकेट)/पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग, भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से
- **ब.** राज्य/भारतीय नर्सिंग परिषद के साथ नर्सेज एवं मिड्वाइफ के रूप में पंजीकृत

**अथवा**

II
- **अ.** भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिड्वाइफरी में डिप्लोमा
- **ब.** राज्य/भारतीय नर्सिंग परिषद में नर्सेज एवं मिड्वाइफ के रूप में पंजीकृत
- **स.** एआईआईएमएस में सभी भाग लेने वालों के लिए उपरोक्तनुसार दर्शित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम 50 शैय्या के अस्पताल में दो वर्षों का अनुभव

**टिप्पणी :** आवश्यक दो वर्ष का अनुभव उपरोक्तनुसार आवश्यक मापदंड है और वैध माना जायेगा, जबकि अनुभव आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त किया गया हो अर्थात् पाठ्यक्रम के रेजीडेंसी अवधि को पूरा करना, परिणाम की घोषणा व राज्य/भारतीय नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकरण के पश्चात्

**आयु सीमा: सभी एम्स के लिए : 18-30 वर्ष के बीच । (सम्बन्धित संस्थान/अस्पताल के भर्ती नियमों के अनुसार आयु शिथिलता के अधीन सामान्य शर्तों में दी गई आयु शिथिलता पर विवरणनुसार)**
सभी के लिए आयु आवेदन प्रपत्र के बंद होते ही अंतिम तिथि पर सगंणित होगी।

**आवेदन शुल्क :**

| | | |
|---|---|---|
| (अ) जनरल/ओबीसी अभ्यर्थी | - | ₹ 3000/- (रुपये तीन हजार मात्र) |
| (ब) एससी/एसटी अभ्यर्थी/ईडब्ल्यूएस | - | ₹ 2400/- (रुपये दो हजार चार सौ मात्र) |
| (स) दिव्यांग | - | निःशुल्क |

- अभ्यर्थी डेबिड कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से विहित आवेदनशुल्क का भुगतान कर सकता है। संव्यवहार/प्रक्रिया शुल्क, यदि कोई है, जैसा लागू हो, अभ्यर्थी द्वारा बैंक को दय होगा।
- **एक बार प्रेषित आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में प्रतिदेय नहीं होगा।**
- विहित शुल्क के बिना आवेदन विचारित नहीं किए जायेंगे तथा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जायेंगे।
- **परीक्षा में उपस्थित होने वाली एससी/एसटी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क नियत समय में परिणाम की घोषणा के पश्चात् लौटा दिए जायेंगे।**

**ऑनलाईन (सीबीटी) पद्धति परीक्षा तिथि : 3 जून 2023 (शनिवार)**

**ऑनलाईन आवेदन एवं नवीनतम सूचना के लिए कृपया एम्स वेबसाईट www.aiimsexams.ac.in देखें।**

**CBC 17112/12/0004/2324**



MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

**विकास एवं सहायता कार्यालय**

**एमएसएमई विकास एवं सहायता कार्यालय, गंगटोक**
**2023 राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार**
**के लिए**
**सिक्किम के योग्य सूक्ष्य, लघु एवं माध्यम उद्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करता है**
**कृपया लॉग इन करें**
httpa://dasboard.msme.gov.in/na
**आवेदन के ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि : 10.05.2023**
**राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कारों का संवर्ग निम्न प्रकार है:**

1. उत्पादन उद्यमिता के लिए पुरस्कार (12 पुरस्कार)
2. सेवा उद्यमिता के लिए पुरस्कार (9 पुरस्कार)
3. महिला उद्यमिता के लिए पुरस्कार (4 पुरस्कार)
4. अ.जा./ अ.ज. जा. श्रेणी के उद्यमिता के लिए पुरस्कार (4 पुरस्कार)
5. दिव्यांगजन श्रेणी उद्यमिता के लिए पुरस्कार (2 पुरस्कार)
6. एनईआर राज्यों के उद्यमिता के लिए पुरस्कार (4 पुरस्कार)

नकद पुरस्कार के अतिरिक्त उद्यमों को ट्रॉफी एवं प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा :
योग्यता एवं उपयुक्तता शर्तें:

- वैध उद्यम पंजीकरण सं.
- वैध पर्यावरण अनुमति प्रमाणपत्र
- औद्योगिक अनुज्ञप्ति (आग/विस्फोटक आदी)
- एवं लिंक में उल्लेखित अनुसार अन्य प्रमाणपत्र

**विस्तृत विवरण के लिए क्लिक करें**
**https://dashboard.msme.gov.in/na/Ent NA Admin/Ent.index.aspx**
**cbc 25113/12/0003/2324**

**संयुक्त निदेशक एवं एचओओ, एमएसएमई- विकास एवं सहायता कार्यालय, तादोंग बाजारी, एन.एच. 10, गंगटोक**
**दूरभाष सं.: 023592-231880**
**ईमेल आईडी: dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in वेबसाइट : www.msmedigangtok.gov.in**



**NAGALAND STATE LOTTERIES**
**Draw Time: 01:00 PM**
**DEAR MAHANADI THURSDAY WEEKLY LOTTERY**
Draw No:4 DrawDate on:27/04/23 Price₹6/-
**1st Prize ₹1 Crore/- 65H 52165**
Cons. Prize ₹1000/- 52165 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
05084 05616 32849 38271 66969 78299 81490 85046 92071 97639
3rd Prize ₹450/-
3245 3579 4127 7304 8022 8205 8480 9000 9106 9783
4th Prize ₹250/-
0323 1542 3575 4568 6258 7933 8058 8293 8930 9336
5th Prize ₹120/-
0109 0247 0253 0297 0345 0377 0402 0594 0620 0756
1338 1360 1537 1625 1934 2006 2073 2076 2085 2127
2181 2216 2271 2310 2312 2552 2955 2988 3002 3006
3065 3274 3305 3325 3349 3548 3652 3681 3911 3951
3973 4030 4326 4452 4520 4706 4792 4834 5028 5049
5052 5058 5402 5427 5694 5799 5944 5951 6028 6234
6328 6539 6659 6720 6748 6852 6903 6968 6976 7139
7161 7224 7381 7602 7896 7918 8056 8177 8268 8452
8563 8564 8910 9040 9057 9158 9161 9191 9211 9397
9403 9429 9585 9643 9666 9699 9773 9888 9927 9960
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE



**NAGALAND STATE LOTTERIES**
**Draw Time: 06:00 PM**
**DEAR LAKE THURSDAY WEEKLY LOTTERY**
Draw No:4 DrawDate on:27/04/23 Price₹6/-
**1st Prize ₹1 Crore/- 82A 08721**
Cons. Prize ₹1000/- 08721 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
09105 16307 35513 37278 38151 52928 53219 76413 85075 99320
3rd Prize ₹450/-
0615 1683 2920 3676 4574 5741 5966 6827 7499 9680
4th Prize ₹250/-
1055 1373 2282 2967 3679 4670 5737 5976 7889 8959
5th Prize ₹120/-
0178 0191 0425 0632 0670 0702 0703 0707 0714 0750
0883 0908 0964 0978 1098 1126 1185 1217 1230 1255
1488 1528 1576 1659 2071 2183 2188 2203 2212 2288
2484 2531 2742 2913 3024 3041 3137 3187 3229 3247
3399 3434 3446 3571 3979 4033 4156 4206 4242 4426
4438 5015 5116 5228 5274 5447 5465 5564 5572 5664
5721 5879 5926 6031 6135 6231 6237 6243 6276 6401
6407 6474 6494 6554 6830 7218 7316 7401 7453 7500
7681 7966 8011 8164 8458 8632 8679 8811 9021 9040
9051 9242 9323 9381 9449 9487 9531 9665 9927 9966
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE



**NAGALAND STATE LOTTERIES**
**Draw Time: 08:00 PM**
**DEAR SANDPIPER THURSDAY WEEKLY LOTTERY**
Draw No:4 DrawDate on:27/04/23 Price₹6/-
**1st Prize ₹1 Crore/- 85G 50772**
Cons. Prize ₹1000/- 50772 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
15328 22957 29283 31309 58387 64711 65982 68093 91768 96454
3rd Prize ₹450/-
0731 1039 1604 1952 2107 4422 6086 6302 6783 9663
4th Prize ₹250/-
2040 2455 4048 4840 5510 5690 6673 7412 8176 9341
5th Prize ₹120/-
0009 0040 0075 0115 0207 0240 0314 0349 0403 0483
0494 0715 0814 0933 1007 1172 1214 1235 1393 1479
1621 1917 1941 2120 2152 2487 2530 2599 2777 2782
2888 2935 2951 3305 3389 3428 3451 3606 3622 3629
3904 3958 4096 4118 4221 4236 4443 4509 4672 4701
4810 5057 5171 5218 5339 5451 5572 5626 5685 5889
6074 6098 6271 6376 6400 6414 6528 6529 6575 6647
6679 6748 6838 7263 7282 7393 7547 7669 7804 7977
8025 8073 8229 8268 8384 8506 8543 8786 8838 8908
8952 8976 9118 9208 9231 9311 9324 9375 9648 9691
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

# मौकापरस्ती की राजनीति

बिहार में एक आईएएस ऑफिसर की हत्या के मामले में जेल काट रहे पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन मंगलवार को रिहा कर दिए गए। खास बात यह कि इस रिहाई का रास्ता उस नीतीश कुमार की सरकार ने साफ किया जो किसी जमाने में सुशासन बाबू की सरकार कही जाती थी। नीतीश कुमार गवर्नेंस को लेकर अपनी साफ छवि के लिए मशहूर थे। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी ही यह मानी जाती थी कि उन्होंने बिहार में कानून का राज कायम किया। हालांकि इस दावे पर सवाल खड़े करने की कोशिशें भी लगातार चलती रहीं, पर नीतीश कुमार बार-बार राजनीतिक पाला बदलते हुए भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास जरूर करते रहे कि इस दावे से उनका साथ पूरी तरह न छूट जाए। दिक्कत यह है कि उनकी सरकार ने जिस तरह से पहले जेल नियमावली में बदलाव के जरिए सरकारी अधिकारियों की हत्या में शामिल लोगों को माफी पाने की पात्रता दिलाई और फिर इसका इस्तेमाल करते हुए आनंद मोहन को जेल से छुटकारा दिला दिया, उसकी किसी और रूप में व्याख्या संभव नहीं है। यह बात सही है कि प्रावधान बदले जाने का फायदा अकेले आनंद मोहन को नहीं, बल्कि उनके साथ-साथ कई अन्य कैदियों को भी हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई। जनहित का ऐसा कौन सा मुद्दा इससे जुड़ा था?

जाहिर है, इस रिहाई की एवज में सवर्ण वोटों के एक बड़े हिस्से में सेंधमारी करने का मकसद छोड़ दिया जाए तो इसका कोई और कारण ढूंढना मुश्किल है। और यही ऐसा बिंदु है जो न केवल नीतीश कुमार को बल्कि आज की समूची राजनीति को कटघरे में खड़ा कर देता है। आनंद मोहन के ही मामले की बात की जाए तो पक्ष-विपक्ष की शायद ही कोई धारा ऐसी हो, जिसने आनंद मोहन का अपने पक्ष में इस्तेमाल नहीं किया। इनकी रिहाई के लिए भी तमाम पार्टियों के लोग बयान देकर माहौल बनाते रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इस मामले में खुद को सबसे अलग और पाक-साफ बताते रहने वाले नीतीश कुमार ने भी खुद अपने चेहरे पर कीचड़ मलने की कवायद की है। कल तक नीतीश और विपक्ष में उनके दूसरे साथी कई मामलों में केंद्र में सत्तासीन बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वे अब उस पर किस मुंह से आपत्ति करेंगे? यह कानून के शासन और संवैधानिक नैतिकता का आग्रह रखने वाले नागरिकों के लिए मायूसी का पल है। राजनीति की सभी धाराओं ने उन्हें निराश किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के इस पतन के पीछे वोट पाने की वही लालसा है, जिसे जातिगत समीकरणों पर आधारित वोटिंग बिहेवियर से खाद-पानी मिलता है। यानी इस बीमारी का इलाज भी अंतिम तौर पर वोटरों के ही पास है।

# जनजाति कानून में संशोधन हो

अवधेश कुमार

लगातार घटती घटनाओं के कारण कुछ ऐसे आंदोलन सुर्खियां नहीं बनते जिन्हें वास्तव में चर्चा में होना चाहिए।

अलग-अलग राज्यों के स्थानीय अखबारों और टीवी चैनलों को देखें तो जनजातियों यानी आदिवासियों के बड़े-बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। आदिवासी शब्द पर विवाद रहे हैं क्योंकि यह भारतीय इतिहास के अनुकूल नहीं है। इसके लिए जनजाति वनवासी शब्द उपायुक्त है। पूरे देश में इन दिनों जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डीलिस्टिंग आंदोलन चलाया जा रहा है। डीलिस्टिंग का अर्थ क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 342- जो अनुसूचित जनजाति के लिए है- उनसे धर्म परिवर्तन करने वालों को बाहर कर दिया जाए। आप अनुसूचित जनजाति की सूची यानी लिस्ट में तभी तक हैं जब तक धर्म नहीं बदला है। जैसे ही आपने धर्म बदला, आपको अनुसूचित जनजाति की सूची से डीलिस्ट यानी बाहर कर दिया जाएगा। इस आंदोलन की रैलियों में उपस्थिति को देखें तो पता चलेगा कि इसे व्यापक समर्थन प्राप्त है। अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी राज्यों की राजधानियों में भी महारैली का आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच कर रहा है। जिन लोगों ने अनुसूचित जनजाति के रोजगार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति पर अध्ययन किया है उनका निष्कर्ष यही है कि ए और बी श्रेणी की ज्यादातर नौकरियां धर्मांतरित ईसाई समुदाय को मिली है। आम अनुसूचित जनजाति के लोग दूसरा धर्म अपनाने के कारण अधिकारों से वंचित हैं।

धर्मांतरित होते हुए भी अनुसूचित जाति का दर्जा पाने वाले लोग प्रभाव से दूसरों को भी अपने धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति से संबंधित है। इसमें धर्मांतरित होते ही संबंधित व्यक्ति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया जाता है। यही प्रावधान अनुच्छेद 342 में नहीं है। मांग यही है कि 342 को भी 341 की तरह संशोधित कर दिया जाए। गहराई से देखें तो इस मांग को स्वीकारने में समस्या नहीं है। जाति की व्यवस्था हिंदू समाज में है। अगर कोई ईसाई या इस्लाम या अन्य धर्म अपनाता है तो उसके साथ उसकी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार संवैधानिक व्यवहार किया जाना चाहिए। जनजातियों के सामने इनसे समस्याएं पैदा हुई हैं, जनजाति सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, अन्य संगठनों के प्रचार से व्यापक जन जागरण भी हुआ है और वे संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। हालांकि यह आंदोलन 2003 से ही आरंभ हो गया था। 2006 में जनजाति सुरक्षा मंच की स्थापना के बाद आंदोलन तेज हुआ। 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को 28 लाख हस्ताक्षरों का ज्ञापन दिया गया, जिसमें सरकार से संविधान में संशोधन कर डीलिस्टिंग की मांग की गई। 30 अक्टूबर, 2018 को कार्तिक उरांव की जयंती पर जिलाधिकारियों को निवेदन किया गया। पिछले वर्ष जनजाति सुरक्षा मंच ने लोक सभा एवं राज्य सभा के सांसदों के बीच अभियान चलाया और 450 सांसदों से भेंट कर यह विषय रखा। इसके बाद कई सांसदों ने दोनों सदनों में इस विषय को उठाया भी।

इसके समानांतर आंदोलन के दूसरे चरण में देश के जनजातीय बाहुल्य 230 जिलों में सुरक्षा मंच ने रैलियों का आयोजन किया। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में 10 लाख से अधिक जनजाति समाज के लोगों ने इनमें भागीदारी की। आंदोलन गांव टोलों तक पहुंच चुका है। देश में लगभग 11 करोड़ जनजाति समाज की आबादी है। इनमें अपनी संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं, श्रद्धा, धर्म आदि को बचाकर रखने वाले धर्मांतरित लोगों के कारण आर्थिक-सामाजिक-विकास में पिछड़ते जा रहे हैं। मूल जनजाति तथा धर्मांतरितों के बीच संघर्ष और टकराव भी सामने आते हैं। देखा जाए तो धर्मांतरित लोग जनजाति कहलाए ही नहीं जाने चाहिए। धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने के कारण जनजाति समाज में विषमता बढ़ी है। अध्ययन यह भी बताता है कि केंद्र सरकार की एक श्रेणी की नौकरियों का ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर के ईसाई बहुल राज्यों को ही मिला है। आबादी कम होने के बावजूद ज्यादातर नौकरियां इनके हिस्से जा रही है। इसका कारण समझना कठिन नहीं है। मध्य भारत के राज्यों की जनजातियां आबादी में कई गुना अधिक होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में काफी पीछे हैं।

जनजाति समूह को चिह्नित करने के लिए लोकुर समिति बनाई गई थी जिसने पांच मानक तय किए- संबंधित समुदाय का प्राचीनतम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से पृथक होना, समाज की मुख्यधारा से संपर्क बनाने में संकोच और आर्थिक पिछड़ापन। लोकुर समिति के मानक को स्वीकार किया जाए तो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम इनका हिस्सा नहीं माने जा सकते। इन पांच मानकों पर धर्मांतरित खरे उतरते ही नहीं। समय-समय पर न्यायालयों ने भी इसके संबंध में फैसले दिए हैं। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन मामले में स्पष्ट लिखा है कि धर्मांतरण के साथ पुरानी परंपरा, रीति, कर्मकांड आदि त्यागने की स्थिति के बाद कोई व्यक्ति जनजाति का दर्जा खो देता है। किसी अनुसूचित जनजाति कैसे माना जाता है? उसकी मूल बातें क्या है? प्रकृति पूजा पहली विशेषता है। ईसाई या इस्लाम धर्म कर्म करने के बाद कोई प्रकृति पूजा कर नहीं सकता। दूसरी विशेषता है, पूर्वजों के रीति-रिवाज का पालन करना। रीति-रिवाजों में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे आयाम हैं, जिनका पालन धर्मांतरित नहीं करते। तीसरा है, आदिवासियों का पहनावा। ईसाई और इस्लाम ग्रहण करने के साथ पहनावा भी बदलने लगता है। जरा दूसरे तरीके से सोचिए।

जब ईसाई और इस्लाम मजहब में जाति व्यवस्था है ही नहीं तो वह रहेगा कैसे। ईसाई या मुसलमान बनने के बाद वह व्यक्ति उस जाति में नहीं रह सकता तो फिर अनुसूचित जनजाति का हिस्सा उसे मानना तर्क की किसी कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। विडंबना देखिए, धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान एक साथ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय का लाभ उठाते हैं। क्या इसे आप संविधान के तहत अवसरों की समानता का उदाहरण मान सकते हैं? समय आ गया है जब पूरे देश के जनजाति समाज की आवाज को स्वीकार कर संवैधानिक व्यवस्था को उसके मूल चरित्र के अनुरूप संशोधित कर दिया जाए।

# खतरनाक हो सकता है जाति का ककहरा पढ़ाना

प्रेमकुमार मणि

अखिल भारतीय कांग्रेस ने अपने रायपुर अधिवेशन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के संबंध में उध्व और महिलाओं तथा युवाओं के संबंध में क्षैतिज अवसर उपलब्ध करने के बारे में फैसला लिया था, तब मुझे अतीव प्रसन्नता हुई थी कि कांग्रेस बदलते हुए हिन्दुस्तान को समझने का प्रयास करने लगी है।

लेकिन हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जाति-जनगणना के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें देख कर निराशा हुई।

प्रतीत होता है, राहुल ने बिहार में चल रही जाति-जनगणना के स्वरूप का समर्थन किया है, जो अपने आप में उलझा हुआ और कुल मिला कर प्रतिगामी कार्यक्रम है। यदि राहुल ने सचमुच जाति जनगणना के बिहार मॉडल का समर्थन किया है, तो यह मेरी दृष्टि से कांग्रेस के लिए खतरनाक है, ठीक वैसे ही जैसे शाह बानो मामले में उसकी गैर-वाजिब दखलंदाजी थी। नतीजतन, कांग्रेस अपनी राजनीति में ढलान की तरफ अग्रसर हो गई। कांग्रेस का जाति-विषयक चिंतन एक बार फिर ऐसे ही मोड़ पर दिख रहा है। इस विषयक जिस बिहार-मॉडल का वह अनुसरण करने जा रही है, अपने मूल में लोकदली-चिंतन है, जिसमें चरण सिंह के जमाने में तो थोड़ी आर्यसमाजी छौंक भी होती थी; लेकिन उनके उपरांत उसकी पृष्ठभूमि केवल खाप-दिमाग वाली रह गई है। इस खाप-दिमाग का अनुसरण कांग्रेस करे, यह राष्ट्रीय राजनीतिक ट्रैजेडी ही कही जाएगी।

जाति और वर्ण के सवाल पर इस मुल्क में पुराने जमाने से विमर्श होते रहे हैं। ठीक-ठीक कोई नहीं जानता कि जाति-वर्ण कब बने। भारतीय इतिहास के पूर्व-मध्यकाल और उसके पहले ज्यादातर भारतीय शासक गैर-ब्राह्मण तबकों से रहे। नंद पहला साम्राज्य था जिसने महाजनपदीय राजनीतिक स्थिति को एक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की। वह शूद्र यानी मिहनतकश तबके से था। मौर्य भी ऐसे ही थे। शुंगों के बारे में जो जानकारी है उनका मूल द्विज था। लेकिन बाद के गुप्त वैश्य थे। पश्चिम में शक और हूण जैसी जातियों के लोग भी शासक बन रहे थे। पूरब में पाल वंश निश्चित तौर पर अद्विज था। दक्खिन में जो कलचुरी थे, वे वैश्य अथवा नापित ( हजाम ) थे। नाग वंश के बारे में इतिहास ने कोई खास जानकारी इकट्ठी नहीं की है लेकिन कश्मीर के अनंतनाग से लेकर दक्कन के नागपुर और असम के इलाकों तक नागवंशियों का इकबाल कायम था। ये प्राय: भारशिव अर्थात शैव थे। इन सबके होते जाति-वर्ण की सामाजिक व्यवस्था बहुत ताकतवर नहीं रही। बौद्धों के रूप में वर्णवाद का एक प्रबल आलोचक पक्ष भारतीय समाज में हमेशा उपस्थित रहा। लेकिन राजपूतों के हिन्दू द्विज व्यवस्था में शामिल होने की अभिलाषा ने वर्णवादी व्यवस्था को राजकीय ताकत दी। इस काल में जाति व्यवस्था को बल मिलना स्वाभाविक था।

सल्तनत और उससे बढ़ कर मुगल काल में सभी हुक्मरानों ने ब्राह्मणवादी जाति-व्यवस्था को इसलिए मजबूत किया कि इससे शासन करने में सुविधा होती थी। भारतीय इतिहास के सिक्ख, जाट सतनामी और डेक्कन के शिवाजी विद्रोह का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं हुआ है। जब अध्ययन होगा और इसके नतीजे आएंगे, तब हमें मालूम होगा कि जाति प्रथा के खिलाफ विद्रोह की जड़ें कितनी गहरी थीं। पूरा भक्ति आंदोलन जाति प्रथा के विरु द्ध दीर्घ आंदोलन के सिवा आखिर है क्या? कबीर, रैदास, नानक आदि कवियों ने जातिवाद के विरुद्ध खुला विद्रोह किया।

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और जातपात पूछे नहीं कोय, हरि को भजै सो हरि का होय का अभिप्राय क्या है? लेकिन इसी दौर में मुगल शासक अपने इस्लामी सामाजिक ढांचे का भी जातिकरण कर रहे थे। क्योंकि अकबर की हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए यह जरूरी कदम था। द्विज हिन्दू संभवत: मुसलमानों से सामाजिक स्तर पर जुड़ने के पूर्व उनके सामाजिक स्तरीकरण के आग्रही थे। नतीजतन मुसलमानों के बीच भी असारफ, अजलाफ और अरजाल का वर्णानुक्रम बन गया। ब्रिटिश राज ने आरंभ में जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक सुधारों पर बल दिया। भारत में अंग्रेजी राज अद्विज जातियों के विद्रोह और सहयोग से संभव हुआ था। 1757 के पलासी, 1799 के मैसूर और 1818 के भीमा-कोरेगांव युद्ध में ब्रिटिश कंपनी फौज का साथ दलित योद्धाओं ने दिया था। इसलिए वे चाहते थे कि भारत में हिन्दू-मुसलमानों के ऊंचे तबकों का प्रभाव खत्म हो। लेकिन 1857 के बाद उनकी मानसिकता बदल गई। भारतीय समाज में फूट डालने के लिए उन्हें जाति व्यवस्था और सांप्रदायिक विभेद को मजबूत करना उपयोगी लगा। 1872 में जब सेन्सस आरंभ हुआ तो तब उन लोगों ने इसका पूरा उपयोग करना चाहा। सेन्सस में जाति को जोड़ना पहली बार 1881 हुआ।

जाति व्यवस्था का विरोध दूसरे स्तर पर विभिन्न रूपों में हो रहा था। महाराष्ट्र में जोतिबा फुले ने भक्तिकाल की ब्राह्मणवाद विरोधी और सामाजिक समत्व की भावना वाले सांस्कृतिक आग्रहों को पुरजोर गति दी। शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना पर उनका जोर था। उनके अनुयायी भीमराव अंबेडकर ने बीसवीं सदी के तीसरे दशक में जातिवाद विरोधी आंदोलन की बागडोर संभाली। उनकी किताब अनीहिलेशन ऑफ कास्ट को समझा जाना चाहिए। आधुनिक शासन-प्रशासन में आरक्षण या भागीदारी जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नहीं, उसे समाप्त करने के लिए होनी चाहिए। इसलिए अंबेडकर की संकल्पना में आरक्षण को अनंतकाल तक के लिए नहीं चलना है। उनका मकसद जातिविहीन समाज है। यह सही है कि जाति के मौजूदा स्वरूप का पर्यास राजनीतिकरण हुआ है। इसके चुनावी जोड़- घटाव की शुरु आत चरण सिंह ने की थी, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के बनिया-ब्राह्मण राजनीति को जवाब देने के लिए अजगर ( अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत) समूह बनाया था। गुजरात में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी ने इसी तर्ज पर पटेलों की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए- क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान-मोर्चा बनाया। इन सबका नतीजा अंतत: क्या निकला? सामाजिक-आर्थिक सवाल गौण पड़े और आधुनिक मूल्यबोध की जगह दकियानूसी मूल्यबोध प्रभावी हुए। समाज प्रगतिशील दौर से दकियानूसी दौर में आ गया। उत्तर प्रदेश और गुजरात आज किसके गढ़ बन गए हैं?

जाति अब वर्ग या जमात बनने लगी है, जो एक आधुनिक सामाजिक ढांचा है। किसी की सामाजिक स्थिति का परिचय ओबीसी, एससी या एसटी जैसे शब्दों से होने लगा है, जो अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है। ओबीसी, एसटी या एससी जाति नहीं वर्ग है। ओबीसी अपने पूरे रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग है, जाति नहीं। जनगणना का ढांचा ऐसा बनाना था कि केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की घोषणा उन्हें करनी होती। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस खाप विचारधारा को कांग्रेस का समर्थन मिला है। जैसे शाह बानो मामले में कांग्रेस के हस्तक्षेप ने मुस्लिम समाज और अंतत: पूरे भारतीय समाज को आधुनिक बोध से हटा कर मध्ययुगीन मूल्यबोध के बीच ला खड़ा किया और नतीजतन, दक्षिणपंथी सोच वाली राजनीतिक पार्टी भाजपा का ग्राफ आगे बढ़ा, वैसे ही जाति जनगणना वाले इस निर्णय से दबंग पिछड़ी जातियों के वर्चस्व-प्राप्त एक छोटे कुनबे का शेष पिछड़े समूहों पर वर्चस्व बढ़ेगा। समाज के आधुनिक की जगह मध्यकालीन मूल्यबोध से जुड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। नई पीढ़ी को जाति का ऐसा ककहरा पढ़ाना खतरनाक हो सकता है।

# विदेश नीति का दमखम

डॉ. आर.के. सिन्हा

सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच चल रहे भीषण गृहयुद्ध के चलते वहां हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में वहां फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने को लेकर सारा देश चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकासी के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। मतलब यह कि अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है।

यह बदले हुए मजबूत भारत का नया चेहरा है। अब जहां पर भी भारतवंशी या भारतीय संकट में होते हैं, तो भारत सरकार पहले की तरह हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठती। आपको याद ही होगा कि रूस-यूक्रेन जंग के कारण हजारों भारतीय मेडिकल छात्र-छात्राएं यूक्रेन में फंस गए थे। उन्हें सरकार तत्काल सुरक्षित स्वदेश लेकर आई। भारत के हजारों विद्यार्थी यूक्रेन में थे। वे वहां पर मेडिकल, डेंटल, नर्संगि और दूसरे पेशेवर कोर्स कर रहे थे। ये रूस-यूक्रेन जंग को देखते हुए वहां से निकल कर स्वदेश आना चाहते थे। पहले तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी अधिक संख्या में यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में पढ़ रहे भारतीय नौजवानों को स्वदेश कैसा लाया जाएगा। पर इच्छाशक्ति हो तो सब कुछ संभव है। यह साबित करके दिखाया गया। अब अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के दिनों की ही बात को जरा याद कर लें। भारतीय वायु सेना और एयर इंडिया के विमान लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर स्वदेश आते रहे थे। भारत के हजारों करोड़ रु पये के प्रोजेक्ट फंस गए थे। इन प्रोजेक्ट्स से हजारों भारतीय जुड़े हुए थे। इन्हीं भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा था।

अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के नियंतण्रके बाद ही आने वाली परिस्थितियों को भांपते हुए भारत सरकार सक्रिय हो गई थी। जाहिर है, ये सब कदम उठाने के बाद भारत सरकार का इकबाल न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी बुलंद हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले 1972 के दौर में चलते हैं। अब भी बुजुर्ग हो रहे भारतीयों को याद ही होगा कि सन 1972 में अफ्रीकी देश युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने अपने देश में रहने वाले हजारों भारतीयों को रातों-रात आदेश दे दिया था कि वे सभी 90 दिनों में देश को छोड़ दें। हालांकि वे भारतीय ही युगांडा की अर्थव्यवस्था की जान थे। पर सनकी अमीन कभी भी और कुछ भी कर देता था।

उसके फैसले से वहां पर दशकों से रहने वाले भारतवंशियों के सामने बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया था। तब ब्रिटेन ने उन भारतीयों को अपने यहां शरण दी थी। तब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने उन भारतवंशियों के लिए कुछ नहीं किया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया यह लोगों को अचम्भे में डालने वाला था क्योंकि, वे कोई कमजोर प्रधानमंत्री तो थी नहीं उस समय बांग्लादेश की आजादी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्म समर्पण के बाद उनकी शोहरत का डंका बज रहा था लेकिन, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। पता नहीं क्यों? भारतीय युगांडा में लुटते-पिटते रहे थे, लेकिन हमने घडियाली आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं किया था। उन भारतीयों को हमसे अभी तक गिला है जो होना भी चाहिए। क्या हम सात समंदर पार जाकर बस गए बहादुर उधमी भारतीयों से सिर्फ यही उम्मीद रखें कि वे भारत में आकर निवेश करें? पर अब भारत चुनौती का सामना करता है।

भारत की बदली हुई विदेश नीति के चलते ही हमने टोगो में जेल में बंद पांच भारतीयों को सुरक्षित रिहा करवाया था। ये सब के सब केरल से थे। भारत सरकार 2015 में यमन में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाई थी। वह अपने आप में एक मिसाल है। अब भारत सरकार के सामने सूडान से भारत के नागरिकों को लाने की बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद सूडान से भारतीयों को वापस लाने के काम पर लगातार नजर रख रहे हैं। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में कुछ भारतीयों के हताहत होने की भी खबरें हैं। सूडान में 3000 से अधिक भारतीय इस समय फंसे हैं। राजधानी खार्तूम में संघर्ष की वजह से इनकी निकासी में मुश्किलें आ रही हैं।

बहरहाल, यह दुखद है कि भारत के मित्र देश सूडान में इतना गंभीर आतंरिक संकट चल रहा है। भारतीय विशेषज्ञ सूडान के वानिकी क्षेत्र के विकास में सन 1910 से सक्रिय हैं। महात्मा गांधी ने 1935 में इंग्लैंड जाते समय पोर्ट सूडान का दौरा किया था और सूडान में बसे भारत वंशियों से मुलाकात की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1938 में सूडान गए थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने 1953 में पहले सूडानी संसदीय चुनाव का निरीक्षण किया। 1957 में स्थापित सूडानी चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव कानूनों और प्रथाओं से प्रेरणा प्राप्त की। भारत ने फरवरी 1954 में स्थापित सूडानीकरण समिति को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसे स्वतंत्रता के बाद सूडानी सरकार में ब्रिटिश कर्मचारियों की जगह लेने का काम सौंपा गया था। भारत ने मार्च 1955 में खार्तूम में अपना दूतावास खोला। सूडान ने उसके चंदेक सालों के बाद राजधानी के चाणक्यपुरी में अपना दूतावास स्थापित किया। अब भारत यह भी चाहेगा कि वहां पर हालात शांतिपूर्ण हो जाएं और वहां से सारे भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया जाए।

# सेहत के लिए बेहद लाभदायक है नींबू पानी

**नींबू पानी को अगर देशी कोल्ड्रिंक कहा जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर यह पेय सेहत और सौंदर्य से जुड़े इतने फायदे देता है, जितने आप सोच भी नहीं सकते। जानिए नींबू पानी के कुछ ऐसे ही फायदे जो आपकी सेहत के लिए बेहद लाभदायक हैं -**

नींबू विटामिन सी का बेहतर स्त्रोत है। साथ ही, इसमें विभिन्न विटामिन्स जैसे थियामिन, रिबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन बी- 6, फोलेट और विटामिन-ई की थोड़ी मात्रा मौजूद रहती है। यह खराब गले, कब्ज, किडनी और मसूड़ों की समस्याओं में राहत पहुंचाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और तनाव को कम करता है। त्वचा को स्वस्थ बनाने के साथ ही लिवर के लिए भी यह बेहतर होता है। पाचन क्रिया, वजन संतुलित करने और कई तरह के कैंसर से बचाव करने में नींबू पानी मददगार होता है। नींबू पानी में कई तरह के मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटैशियम और जिंक पाए जाते हैं।

## किडनी स्टोन

नींबू पानी का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, इसका किडनी स्टोन से राहत पहुंचाना। मुख्यरूप से किडनी स्टोन शरीर से बिना किसी परेशानी के निकल जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह यूरीन के बहाव को ब्लॉक कर देते हैं जो अत्यधिक पीड़ा का कारण बनता है। नींबू पानी पीने से शरीर को रिहाइड्रेट होने में मदद मिलती है और यह यूरीन को पतला रखने में मदद करता है। साथ ही यह किडनी स्टोन बनने के किसी भी तरह के खतरे को कम करता है।

## डायबिटीज

नींबू पानी, हाई शुगर वाले जूस व ड्रिंक का बेहतर विकल्प माना जाता है। खासतौर से उनके लिए जो डायबिटीज के मरीज हैं या वजन कम करना चाहते हैं। यह शुगर को गंभीर स्तर तक पहुंचाए बिना शरीर को रिहाइड्रेट व एनर्जाइज करता है।

## पाचनक्रिया में फायदेमंद

नींबू पानी में मौजूद नींबू का रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पित्त सिक्रेशन के प्रोडक्शन में वृद्धि करता है, जो पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही यह एसिडिटी और गठिया के खतरे को भी कम करता है। जो लोग आमतौर पर पाचन-संबंधी समस्याओं जैसे एबडॉमिनल क्रैम्प्स, ब्लॉटिंग, जलन और गैस की समस्या आदि से परेशान होते हैं, उन्हें नियमित रूप से नींबू पानी का सेवन करना चाहिए।

## कब्ज

अगर आपको कब्ज की समस्या है, तो नींबू पानी आपके लिए बेहद फायदेमंद है। प्रतिदिन सुबह गर्म नींबू पानी पिएं और पूरे दिन कब्ज की समस्या से दूर रहें।

## इम्यून सिस्टम

नींबू पानी बायोफ्लेवोनॉयड, विटामिन सी और फाइटोन्यूट्रियंट्स का बेहतर स्रेत है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स के कारण यह शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है।

## खराब गला

नींबू पानी को गुनगुना करके पीने से गले की खराबी या फैरिन्जाइटिस में आराम पहुंचाता है।

## वजन

हर सुबह शहद के साथ गुनगुना नींबू पानी पीने से अतिरिक्त वजन आसानी से कम किया जा सकता है।

## मसूड़ों की समस्या

नींबू पानी पीने से मसूड़ों से संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। नींबू पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पीने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

# कैसे पहचानें कि इम्यून सिस्टम है कमजोर

**इम्यून सिस्टम के मजबूत होने पर हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। यदि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो यह हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है बल्कि हैपेटाइटिस, लंग इंफेक्शन, किडनी इंफेक्शन सहित और कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि कई बार यह होता है इम्यून सिस्टम कमजोर तो होता है, पर हम इसे समझ ही नहीं पाते। आखिर कैसे पहचान करें कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आइए जानते हैं।**

अगर आपको लगता है कि आप बार-बार बीमार हो रहे हैं और जुकाम की शिकायत रहती है। बार-बार सर्दी हो जाना और यदि आपके आस-पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे खांसी है और आपको भी इससे जल्दी खांसी या सर्दी हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। बदलते मौसम का आपको बीमार करना आपके कमजोर इम्यून सिस्टम को दर्शाता है। यदि आप मौसम के बदलने पर बीमार हो रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। व्यायाम करते समय सांसों का फूलना व जल्दी थक जाना यह कमजोर इम्यून सिस्टम की निशानी है। नींद न आना, आंखों के नीचे काले घेरे, थकान महसूस होना- यह भी कमजोर इम्यून सिस्टम की निशानी है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की अपेक्षा बार-बार बीमार होते हैं, जुकाम की शिकायत रहती है, खांसी, गला खराब होना या स्किन रैशेज जैसी समस्याएं रहती हैं तो बहुत पॉसिबल है कि यह आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हो। कैंडिडा टेस्ट का पॉजिटिव होना, बार-बार यूटीआई, डायरिया, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले वगैरह भी खराब इम्यूनिटी के लक्षण हैं।

# आयुर्वेद के अनुसार तेज भूख लगने पर कभी खाली पेट न खाएं ये चीजें

कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत तेज भूख लग जाती है और हम उस वक्त हमें जो भी उपलब्ध होता है, वो खाने लग जाते हैं लेकिन ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक तेज भूख लगने पर कुछ ऐसी चीजें है, जिन्हें नहीं खाना चाहिए।आइए, जानते हैं कौन-सी हैं वो चीजें-

## अमरुद

अमरुद एक ऐसा फल है, जिसे अलग-अलग स्थितियों में खाने पर अलग-अलग परिणाम देखने को मिलते हैं यानी अगर आप सर्दियों में सुबह के वक्त खाली पेट अमरुद खाएंगे, तो आपको पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। वहीं, गर्मी में खाली पेट अमरूद खाएंगे, तो यह फायदा देता है। ऐसे में आपको खाली पेट अमरूद नहीं खाना चाहिए।

## सेब

सर्दियों में खाली पेट सेब खाने से बीपी बढ़ सकता है, अगर सुबह सबसे पहले यानी बिना कुछ खाए आप सेब खा लेते हैं, तो इस दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है लेकिन गर्मी में आप खाली पेट सेब खा सकते हैं।

## टमाटर

टमाटर की तासीर गर्म होती है। इसे आप सर्दी के मौसम में तो खाली पेट खा सकते हैं लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा करने पर पेट में या सीने में जलन की समस्या हो सकती है। आपको सुबह के समय टमाटर खाने से परहेज करना चाहिए।

## चाय-कॉफी

चाय या कॉफी को खाली पेट पीने से बचना चाहिए।आप चाय या कॉफी को बिस्किट, ब्रेड के साथ ले सकते हैं लेकिन खाली पेट या तेज भूख लगने पर सिर्फ चाय-कॉफी न लें, इससे आपके पेट में गैस बन सकती है।

## दही

बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें दही फायदे की जगह पर हानि पहुंचा देती है।ऐसे में दही को सुबह के समय खाली पेट खाने से बचना चाहिए, वर्ना आपकी सेहत बिगड़ सकती है।

# अमृत है आंवला 10 बेहतरीन फायदे

विटामिन-सी से भरपूर आंवला, हर मौसम में लाभदायक होता है। यह आंखों, बालों और त्वचा के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही इसके और भी कई फायदे हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर आंवले का प्रयोग अचार, मुरब्बा या चटनी के रूप में किया जाता है,लेकिन इसका अलग-अलग तरह से सेवन आपके लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप नहीं जानते इस अनमोल फल के बारे में तो जरूर पढ़िए -

- डायबिटीज के मरीजों के लिए आंवला बहुत काम की चीज है। पीड़ित व्यक्ति अगर आंवले के रस का प्रतिदिन शहद के साथ सेवन करे तो बीमारी से राहत मिलती है।
- एसिडिटी की समस्या होने पर आंवला बेहद फायदेमंद होता है। आंवला का पाउडर, चीनी के साथ मिलाकर खाने या पानी में डालकर पीने से एसिडिटी से राहत मिलती है। इसके अलावा आंवले का जूस पीने से पेट की सारी समस्याओं से निजात मिलती है।
- पथरी की समस्या में भी आंवला कारगर उपाय साबित होता है। पथरी होने पर 40 दिन तक आंवले को सुखाकर उसका पाउडर बना लें, और उस पाउडर को प्रतिदिन मूली के रस में मिलाकर खाएं। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में पथरी गल जाएगी।
- रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर, प्रतिदिन आंवले के रस का सेवन करना काफी लाभप्रद होता है। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, और खून की कमी नहीं होने देता।
- आंखों के लिए आंवला अमृत समान है, यह आंखों की रौशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके लिए रोजाना एक चम्मच आंवला के पाउडर को शहद के साथ लेने से लाभ मिलता है और मोतियाबिंद की समस्या भी खत्म हो जाती है।
- बुखार से छुटकारा पाने के लिए आंवले के रस में छौंक लगाकर इसका सेवन करना चाहिए, इसके अलावा दांतों में दर्द और कैविटी होने पर आंवले के रस में थोड़ा सा कपूर मिला कर मसूड़ों पर लगाने से आराम मिलता है।
- शरीर में गर्मी बढ़ जाने पर आंवल सबसे बेहतर उपाय है। आंवले के रस का सेवन या आंवले को किसी भी रूप में खाने पर यह ठंडक प्रदान करता है। हिचकी तथा उल्टी होने की पर आंवले के रस को मिश्री के साथ दिन में दो-तीन बार सेवन करने से काफी राहत मिलेगी।
- याददाश्त बढ़ाने में आंवला काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए सुबह के समय आंवला के मुरब्बा गाय के दूध के साथ लेने से लाभ होता है, इसके अलावा आप प्रतिदिन आंवले के रस का प्रयोग भी कर सकते हैं।
- चेहरे के दाग-धब्बे हटाकर उसे खूबसूरत बनाने के लिए भी आंवला आपके लिए उपयोगी होता है। इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ, चमकदार होती है और झुर्रियां भी कम हो जाती हैं।
- बालों को काला, घना और चमकदार बनाने के लिए आंवले का प्रयोग होता है, इसके पाउडर से बाल धोने या फिर इसका सेवन करने से बालों की समस्याओं से निजात मिलती है

# नाश्ते में इन पांच चीजों को खाने से तेजी से बढ़ता है वजन, ज्यादातर लोग करते हैं सेवन

फिटनेस पाने के लिए लोग क्या-क्या जतन करते हैं। कई सर्वे के अनुसार आप शरीर पर चर्बी होने के कारण कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको बैली फैट कम करने के साथ फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को फिट रखने में ब्रेकफॉस्ट का भी अहम रोल होता है, ऐसे में आपको अगर हमेशा स्लिम ट्रिम रहना है, तो ऐसी 5 चीजें हैं, जो आपको नाश्ते में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए-

**वाइट ब्रेड** - ब्रेड ज्यादातर भारतीय घरों में खाई जाती है लेकिन आपको बता दें कि ब्रेड का ज्यादा सेवन करना न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है बल्कि इससे आपका वजन भी बढ़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि वाइट की जगह ब्राउन ब्रेड का सेवन करे।

**प्रोसेस्ड फूड** - ऐसे खाद्य पदार्थों को कई बार पकने की क्रिया से गुजरना पड़ता है। साथ ही तेल, मसाले, घी होने की वजह से ये सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। आपको चिप्स, पॉपकॉर्न, ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स आदि से दूर रहना चाहिए।

**केक, कुकीज** - केक और कुकीज में मैदे के अलावा घी और क्रीम का इस्तेमाल होता है, जो आपकी फिटनेस के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है इसलिए आपको नाश्ते में इन चीजों को नहीं खाना चाहिए।

**नूडल्स** - नूडल्स खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन इसे हेल्दी ब्रेकफॉस्ट नहीं माना जा सकता है, इसी वजह से आपको नूडल्स नाश्ते में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए।

**फ्रूट जूस** - आपको कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट में उपलब्ध फ्रूट जूस बिल्कुल न पिएं बल्कि आप घर में ही फलों का जूस निकालकर पी सकते हैं। आपके पास अगर जूस की जगह फल खाने का समय है, तो नाश्ते के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा।

**पकौड़े-कचौड़ी** - सुबह-सुबह तली चीजें खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप पकौड़े और कचौड़ी जैसी तली हुई चीजें सुबह नहीं खाएंगे, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा।

# आंखों को थकान से राहत देगा गुलाब जल, कम होगा तनाव

**वर्क के दौरान लैपटाप का ज्यादा इस्तेमाल न केवल आपके पूरे स्वास्थ्य पर असर डालता है बल्कि इसका असर आपकी नाजुक आंखों पर भी पड़ता है।**

वर्क के दौरान लैपटाप का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं इसी के साथ ही मोबाइल के संपर्क में भी हम ज्यादा रह रहे हैं जिससे आंखों में जलन, धुंधला दिखना व खुजली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखों की देखभाल करें और जब भी आंखों पर दबाव महसूस करें तो स्क्रीन से दूर हो जाएं और बीच-बीच में आंखों को ठंडे पानी से भी धोते रहें। आंखों की जलन की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। भले ही इस वक्त आप घर पर हैं लेकिन आंखों में जलन आप महसूस करते होंगे। इसलिए इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको अपनी आंखों की सही देखभाल की जरूरत है, वहीं गुलाब जल का इस्तेमाल आपको आंखों की समस्या से निजात दिला सकता है। गुलाब जल के इस्तेमाल से आंखों को ठंडक मिलती है, साथ ही ताजगी महसूस होती है। ओवरटाइम काम करने के दौरान आंखों में तनाव महसूस होता है इसके लिए खुद को रिलेक्स करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कॉटन में गुलाब जल डालें और इसे अपनी आंखों पर रखकर कुछ देर के लिए आंखों को आराम दें। गुलाब जल को आंखों में डालने से भी तुरंत राहत मिलती है, साथ ही फ्रेश महसूस होता है। अत : अपने आंखों का ध्यान रखें और समय-समय पर अपनी पलकों को झपकाते रहें।

## शराब घोटाले मामले में ईडी ने कोर्ट में दाखिल किया पूरक आरोप पत्र, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप सिंह ढल के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष इस मामले में तीसरा पूरक आरोपपत्र शुक्रवार को विचार के लिए आने की संभावना है।

ईडी ने ताजा चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया, अभी वह इस समय इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है और बाद में उन पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

नवीनतम चार्जशीट के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद के व्यवसायी पिल्लई भारत राष्ट्र समिति एमएलसी के कविता के करीबी सहयोगी थे और उन्हें मामले में अन्य आरोपियों के साथ मामले का सामना करना होगा।

व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे, जो विभिन्न प्रकार के शराब ब्रांडों और संबंधित पेय पदार्थों का एक प्रमुख आयातक और वितरक था। वहीं सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को अदालत अपना आदेश सुना सकती है।

## दिग्विजय का सिंधिया का तंज, कहा- कांग्रेस में महाराजा थे बीजेपी में सिर्फ भाई साहब

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज गुरुवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनके साथ महाराजा जैसा व्यवहार किया जाता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद उन्हें सिर्फ 'भाई साहब' होने के स्तर तक कम कर दिया गया है। ग्वालियर शाही परिवार के वंशज सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया को 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

यहां धार जिले में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे सिंधिया पार्टी छोड़ देंगे। साथ ही सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को भगवा संगठन में अपनी मौजूदा 'स्थिति' के बारे में सोचना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी के पूर्व साथी सिंधिया के पाला बदलने और इससे प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने पर उन्हें खेद है, तो राज्यसभा सदस्य सिंह ने कहा, निश्चित रूप से, हमें खेद है। हमने उनसे (सिंधिया से) हमें छोड़ने की उम्मीद नहीं की थी। दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिंधिया को बहुत कुछ दिया।

उन्होंने कहा, मैं और अर्जुन सिंह (पूर्व मुख्यमंत्री) उनके पिता (माधवराव सिंधिया) को कांग्रेस में लाए। उन्हें (ज्योतिरादित्य सिंधिया) पूरा सम्मान दिया। पार्टी में उनको बढ़ावा दिया, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया। एआईसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) का महासचिव बनाया। हमने महाराजा की तरह उनका सम्मान किया। अब भाजपा ने उन्हें सिर्फ भाई साहब बना दिया है इसलिए उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए।'

दिसंबर 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार मार्च 2020 में सिंधिया के प्रति वफादार विधायकों के एक समूह के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के बाद गिर गई थी। इसके बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बदनावर कस्बे में पहुंचे थे। कांग्रेस ने 2018 में बदनावर विधानसभा सीट जीती थी लेकिन स्थानीय विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए और भाजपा (जिसने दत्तीगांव को मैदान में उतारा) ने बाद के उपचुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। दत्तीगांव प्रदेश की भाजपा सरकार में अब मंत्री हैं।

2019 के पुलवामा आतंकी हमले और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा उठाए गए सवालों का जिक्र करते हुए, कांग्रेस सांसद सिंह ने कहा कि जब उन्होंने अतीत में खुद इस मुद्दे पर बात की थी, तो भाजपा ने उन्हें 'पाकिस्तानी और राष्ट्र-विरोधी' करार दिया था। उन्होंने इस साल जनवरी में कहा था, 'पुलवामा हमला हुआ। हमारे सीआरपीएफ के चालीस जवान शहीद हो गए। वे क्यों मारे गए? सीआरपीएफ निदेशक ने अनुरोध किया कि यह (पुलवामा) एक संवेदनशील क्षेत्र है और सीआरपीएफ जवानों को विमान के माध्यम से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने इससे इनकार किया। उन्होंने मना क्यों किया। सिंह ने बताया कि मलिक ने अब वहीं बात कही है।

उन्होंने कहा, अब, जब वही बात (पूर्व) राज्यपाल द्वारा कही गई है, उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया था। इसी तरह, जब हमने अडाणी मुद्दे (अमेरिका में स्थित एक कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट पर) पर बात की तो हमें चुप रहने के लिए कहा गया। केवल तानाशाह ही चुप रहने के लिए कहता है। यह लोकतंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा नहीं है।

व्यापमं भर्ती घोटाले के संबंध में की गई टिप्पणियों को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मामले में भोपाल की एक विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि आरोप लगाना उनका अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, दिग्विजय सिंह बहुत सोच विचार के बाद ही कोई बयान देता है। बुधवार को धार में एक महिला की हत्या के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने इस अपराध के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।

## केजरीवाल के बंगले की सजावट पर करोड़ों खर्च, कांग्रेस बोली- मतदाताओं के गाल पर तमाचा

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाने को लेकर गूरूवार को उन पर तीखा प्रहार किया।

केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाने को लेकर कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल का यह कदम शर्मनाक और मतदाताओं के गाल पर तमाचा है।

पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, आप (केजरीवाल) खुद को आम आदमी कहते हैं। अब तो खैर कोई आम आदमी मानता नहीं है। कोविड के समय जब दिल्ली में त्राहि-त्राहि मची हुई थी तब आपने 45 करोड़ रुपये अपने आवास पर खर्च कर दिए। ये होती है आम आदमी की सरकार? ये चौंकाने वाला तथ्य है।

उन्होंने कहा, हम इससे हैरान नहीं हैं क्योंकि हम इनकी असलियत जानते थे। यह कैसी आम आदमी की सरकार है जो अपने सादगी के ढोल-नगाड़े पीटती थी? खेड़ा ने कहा, एक मुख्यमंत्री के बंगले पर 45 करोड़ रुपये खर्च होना शर्मनाक है। वोटर के गाल पर तमाचा मार रहे हैं। इससे कम कुछ नहीं है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कुल 44 178 करोड़ रुपये सिविल लाइंस में छह-फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित केजरीवाल के सरकारी आवास के अतिरिक्त निर्माण या बदलाव पर खर्च किए गए। दस्तावेजों के मुताबिक, यह राशि नौ सितंबर, 2020 से जून, 2022 के बीच छह किस्तों में खर्च की गई।

## भाजपा की आप को चुनौती, बिधूड़ी ने कहा- केजरीवाल के जेल जाने तक जारी रहेगा संघर्ष

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण में कथित सरकारी धन के दुरुपयोग के खिलाफ भाजपा ने लगातार दूसरे दिन विरोध दर्ज कराया। भाजपा ने चुनौती दी है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री निवास के पास एकजुटता दिखाते हुए भाजपा सांसदों सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से मंच पर महलनुमा फोटो लगाया गया और सामने मुख्यमंत्री के चेहरे का मुखौटा पहने एक व्यक्ति को बिठाकर विरोध जताया गया।

इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आप सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जल बोर्ड घोटाला, बिजली सब्सिडी, डीटीसी, कच्चे कमरे बनवाने में घोटाला किया गया व अब बंगले की मरम्मत करवाने में एक और घोटाला कर केजरीवाल ने सभी हदें पार कर दी हैं। मुख्यमंत्री के इशारे पर ही हवाला कारोबारियों के साथ सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री जल्द ही जेल जाएंगे। उनके जेल जाने तक भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली को लूटने वाले गजनवी और गोरी का जो हाल हुआ, वही एक दिन दिल्ली की जनता केजरीवाल का करेगी।

वहीं, सांसद डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि जब पूरी दिल्ली कोरोना के खौफ से कांप रही थी तो केजरीवाल घर से किसी भी अस्पताल को देखने तक नहीं गए, क्योंकि वह अपना बंगला बनवाने में व्यस्त थे। दुनिया के सबसे बेइमान, झूठे और धोखेबाज मुख्यमंत्री के खिलाफ हमें संकल्प लेना होगा कि जब तक वे इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम भाजपा के सिपाही हैं और हम कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट नहीं बांटते, बल्कि हम ईमानदारी से जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। केजरीवाल ने अपने राजमहल में एक-एक पर्दा 8 लाख रुपये में लगवाया है, लेकिन हमारे घर में लगे पर्दे की कीमत मात्र 225 रुपये हैं। दिल्ली को लूटने का काम मुख्यमंत्री ने किया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार में आने से पहले कहते थे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, लेकिन आज उन्होंने अपने महल की मरम्मत में 45 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। बच्चों की सौगंध लेने वाले केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन लेने से पीछे नहीं हटे।

प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल, दिनेश प्रताप सिंह व हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये राजमहल में लगाने वाले मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। शराब घोटाला किया। अब राजमहल के मरम्मत का भ्रष्टाचार भी उजागर हो गया है। भ्रष्टाचार का नतीजा है कि दो-दो मंत्री तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं।

## हताश कांग्रेस सत्ता पाने के लिए छटपटारही है : स्मृति ईरानी

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए छटपटा रही है और वह सीमावर्ती खानापुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से लोगों को ला रही है। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस मराठी भाषी बहुल इस क्षेत्र में मराठी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां उसने कोई विकास नहीं किया।

ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अन्य वंचित समुदायों की कीमत पर धर्म के आधार पर आरक्षण को बढ़ावा दिया और अब जब कर्नाटक सरकार ने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया तो पार्टी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। खानापुर बेलागावी जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। बेंगलुरु शहर के बाद इस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीट आती हैं। ईरानी 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में जिले की यात्रा पर हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यहां तकरीबन छह हजार लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की गरीबों को सपने दिखाने की आदत रही है। यह सपने दिखाकर राजनीति करती रही है और उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर भी इसने 40 साल तक ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, मैंने राहुल गांधी को उनके गढ़ (अमेठी) में हराया। राहुल गांधी वहां 15 साल तक थे, जबकि गांधी परिवार 40 साल तक वहां रहा। मैं साधारण परिवार से संबंध रखती हूं और उन्हें हराने वहां गई थी।

ईरानी ने कहा कि कांग्रेस खानपुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए भ्रम पैदा कर रही है, लेकिन भाजपा विकास कार्य करने के लिए यह सीट जीतना चाहती है। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस महाराष्ट्र के लोगों को खानापुर में चुनाव लड़ने के लिए ला रही है।

कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए समर्पित कार्यकर्ता क्यों नहीं मिल पा रहे? इसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि मराठी भाषी लोग कभी भी उस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे जिसने हिन्दुत्व विचारक वीर सावरकर का अपमान किया है और दूसरा वे राहुल गांधी पर विश्वास नहीं करेंगे जो ज्यादातर समय विदेश यात्रा करने में बिताते हैं और चुनाव से ठीक पहले दिखाई देते हैं।

खानापुर में कुल 2.11 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1.09 लाख पुरुष और 1.02 लाख महिलाएं हैं। यहां भाजपा प्रत्याशी विट्ठल राव हलगेकर और कांग्रेस की अंजलि निंबालकर के बीच सीधा मुकाबला है।

## भारत रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। भारत पिछले साल रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का चौथा देश रहा। भारत ने वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में छह प्रतिशत अधिक राशि खर्च की।

यह जानकारी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) ने अपनी रिपोर्ट में दी है।

सैन्य व्यय रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने कुल रक्षा बजट की करीब 23 प्रतिशत राशि उपकरणों और अवसंरचना विकास पर व्यय की जिसमें चीन से लगती सीमा पर व्यय शामिल है जहां पर पड़ोसी देश के साथ तनाव चल रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा बजट का अधिकतर हिस्सा वेतन और पेंशन पर व्यय हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2022 में कुल 81.4 अरब डॉलर की राशि रक्षा पर खर्च की जो वर्ष 2021 के मुकाबले छह प्रतिशत और वर्ष 2013 के मुकाबले 47 प्रतिशत अधिक है।

सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया, भारत के रक्षा बजट में वृद्धि चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर मौजूद तनाव को प्रतिउबबित करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2022 के दौरान दुनियाभर में रक्षा पर होने वाले खर्च में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत है।

इसके बाद 13 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ चीन का स्थान आता है। रूस, भारत और सऊदी अरब क्रमश: 3.9 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत रक्षा व्यय के साथ तीसरे, चौथे और पांचवे स्थान पर हैं। वर्ष 2022 में वि के रक्षा व्यय में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी शीर्ष पांच देशों की है।

## राज ठाकरे को राहत, हेट स्पीच मामले में समन खारिज, कोर्ट ने कहा- धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक नहीं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। दिल्ली हाईकोर्ट से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे को राहत मिली। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को बोकारो की एक अदालत द्वारा कथित अभद्र भाषा के मामले में जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आस्था और धर्म का पालन करना अधिक लचीला है और इसे किसी व्यक्ति के विचारों से आहत या उकसाया नहीं जा सकता है। अदालत ने यह आदेश 13 मार्च को दिया था, जिसे गुरुवार को जारी किया गया।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि भारत की एकता इसके विभिन्न धर्मों, आस्थाओं और भाषाओं के 'सह-अस्तित्व' में निहित है और वह धर्म और आस्था, जो सदियों से जीवित है और रहेगी, मनुष्य की तरह नाजुक नहीं हैं। एक अलग आदेश में न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, दंगा और अभद्र भाषा के कथित अपराधों के लिए ठाकरे को धनबाद की एक अदालत द्वारा जारी किए गए समन को भी रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि बोकारो अदालत द्वारा 2008 में पारित समन आदेश केंद्र या झारखंड सरकार की पूर्व मंजूरी की कमी के कारण बरकरार नहीं रखा जा सकता है। लेकिन की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना आदि) और 153बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकीकरण के प्रतिकूल दावे) के तहत कथित अपराधों के लिए ठाकरे के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया।

यह मामला ठाकरे के 2008 के एक भाषण से जुड़ा हुआ है जब उन्होंने कथित तौर पर 'छठ पूजा' को एक 'नाटक' और 'संख्यात्मक शक्ति का प्रदर्शन' की संज्ञा दी थी। छठ पूजा हिन्दुओं का एक त्योहार है और यह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मनाया जाता है।

हाईकोर्ट में ठाकरे का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी और अनुपम लाल दास ने किया। कथित बयान के संबंध में कई मामले बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न राज्यों से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे। अलग-अलग आदेशों में अदालत ने त्योहार को लेकर किए गए टिप्पणी पर छह अन्य लंबित आपराधिक शिकायतों में ठाकरे को जारी किए गए समन को भी रद्द कर दिया, लेकिन शिकायतों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

धनबाद अदालत में की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अक्टूबर 2008 में ठाकरे के भाषण के बाद कई लोग जबरन हावड़ा-बॉम्बे मेल में घुस गए थे और हंगामा किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अदालत ने 2008 और 2009 में पारित समन आदेशों को दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मंजूरी की कमी के आधार पर रद्द कर दिया।

## 'ममता पुलिस ने की युवक की निर्मम हत्या', शुभेंदु अधिकारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कोलकाता, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि राज्य की पुलिस ने कलियागंज इलाके में एक राजबंगशी युवक की हत्या की है। अधिकारी ने कहा कि राज्य में अशांति फैल रही है और लोगों से अपील की कि वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'ममता' पुलिस ने कलियागंज में 33 वर्षीय राजबंगशी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। ममता पुलिस ने भाजपा पंचायत समिति सदस्य बिशनु बर्मन के घर पर रात ढाई बजे छापेमारी की, जब घर पर बिशनु बर्मन नहीं मिला तो उन्होंने राजबंगशी युवक मृत्युंजय बर्मन (33 वर्षीय) की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। यह राज्य आतंक की सबसे बुरी स्थिति है और ममता बनर्जी सम्राट नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे हैं और राज्य जल रहा है और नागरिक अशांति की तरफ जा रहा है।'

'ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कलियागंज के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कही थी। कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उसका पालन कर दिया। राज्य द्वारा की गई इस निर्मम हत्या की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने आगे लिखा कि लोगों को ऐसे हिंसा और खून खराबे के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए।'

बता दें कि उत्तर दिनाजपुर के कलियागंज में हाल ही में एक नाबालिग किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस पर पथराव किया। जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस मामले पर सियासत भी जारी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कलियागंज की घटना पर कहा कि जब से कलियागंज में दुष्कर्म और हत्या हुई है, तब से पुलिस भाजपा के वोटबैंक पर अत्याचार कर रही है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी

के आदेश पर यह हो रहा है। बीती रात वहां लोगों को गिरफ्तार पुलिस गई थी और उसी दौरान उन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। हम इसका विरोध करेंगे।

भाजपा नेता देबाश्री चौधरी ने कहा कि उत्तरी दिनाजपुर के कलियागंज कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हमारे कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं को राम नवमी हिंसा मामले में लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी की असफलता के चलते कलियागंज की घटना हुई और अब उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

## बुलेट ट्रेन से भी जुड़ेगा नोएडा का मेडिकल डिवाइस पार्क, पोड टैक्सी, मेट्रो और हाईवे से मिलेगी बेहतरीन कनेक्टिविटी

**नोएडा ।** यूपी सरकार प्रदेश को मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 28 में 350 एकड़ में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क को बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जहां मेट्रो, एक्सप्रेस वे, ट्रांसपोर्ट नगर ही नहीं बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी के साथ भी जोड़े जाने की तैयारी है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अबतक 59 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। वहीं 26 आवंटियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से आवंटन पत्र व चेकलिस्ट और लीज प्लान सौंपे गये हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि भूखंडों के आवंटियों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उन्हें भूमि आवंटन से संबंधित पत्र सौंपे गये हैं। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस मेडिकल डिवाइसेज पार्क को विश्व स्तरीय सुविधा संपन्न बनाने पर तेज गति से काम हो रहा है।

पार्क में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना भी की जा रही है। इससे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट ग्रांट, एमएआई ग्रांट आदि कार्यों के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का निर्माण कार्य भी प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण का यह क्षेत्र बेहतर रोड, मेट्रो, हाईवे, पोड टैक्सी और बुलेट ट्रेन से भी कनेक्टेड होने जा रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार यहां कॉमन हाइड्रैंट फैसिलिटी की सुविधा प्रदान की जायेगी। हाईवे पर साइनेज की व्यवस्था करने के लिए महाप्रबंधक परियोजना को निर्देशित किया गया है। साथ ही आवंटियों को अवगत कराया गया है कि इस योजना के निकटवर्ती गांवों में और प्राधिकरण क्षेत्र में बने सेक्टर में आवासीय सुबिधा उपलब्ध है।

## लाइक और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नोएडा के युवक ने फेसबुक पर डाला ऑल आउट पीते हुए वीडियो, अलर्ट के बाद पुलिस पहुंची घर

**नोएडा ।** अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने और साथ-साथ अपने फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स और लाइक की संख्या बढ़ाने के लालच में एक युवक ने इतना बड़ा प्रैंक किया की आधी रात को पुलिस उसके घर पहुंच गई। उसको समझा-बुझाकर उसकी काउंसलिंग कर उसे उसके परिजनों के हवाले किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, फेसबुक पर लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के उद्देश्य से आत्महत्या करने संबंधी पोस्ट डालने वाले युवक (20) की सूचना पुलिस को मिली थी। जिसके बाद सोशल मीडिया सेल व थाना फेस-2 पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर युवक की तलाश की और काउंसलिंग करने के पश्चात समझा बुझाकर उसे परिजनों के सुपुर्द किया गया। जानकारी के मुताबिक, 25/26 अप्रैल की देर रात्रि करीब 12:45 बजे सोशल मीडिया सेल को डीजीपी मुख्यालय मीडिया सेल से एक वीडियो और मोबाईल नंबर प्राप्त हुए। विडियो में एक युवक उम्र करीब 20 वर्ष द्वारा ऑल आउट (मच्छर मारने का जहरीला द्रव) हाथ में लेकर उसको पीता हुआ देखा जा रहा है। उक्त वीडियो और मोबाईल नंबर प्राप्त होते ही सोशल मीडिया सेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई, तो उसकी लोकेशन सेक्टर-87 के आस-पास मिली। जिसपर सोशल मीडिया सेल टीम द्वारा तत्काल थाना प्रभारी फेस-2 को अवगत कराया गया। देर रात्रि होने के कारण थाना फेस 2 पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुए आसपास करीब 50 से अधिक लोगों से जानकारी करने के बाद पुलिस उस युवक का घर खोज लिया गया। जिसके बाद थाना प्रभारी फेस-2 द्वारा युवक से उपरोक्त पोस्ट करने के संबंध में जानकारी की गई। युवक द्वारा बताया गया की फेसबुक पर लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के उद्देश्य से उसके द्वारा रील बनाते हुए ऑल आउट में पानी डालकर पीते हुए एक इमोशनल वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया में रील बनाकर डाला गया था।

## दिल्ली में सफर करने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 28 अप्रैल से 20 दिनों के लिए बंद रहेगा यह पुल

**नई दिल्ली।** दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि कुछ मरम्मत कार्य के कारण निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले बारापुल्ला नाला पर पुल का कैरिजवे 28 अप्रैल से 20 दिनों के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को 28 अप्रैल से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में कहा कि नीला गुंबद की तरफ से आने वाले यात्री निक्कू चौक/राजदूत लाल बत्ती के रास्ते निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए होटल प्रीत पैलेस के पास बाएं मोड़ से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ओर विपरीत कैरिजवे ले सकते हैं। हालांकि, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ से नीला गुंबद आने वाले यात्रियों को मथुरा रोड टी-प्वाइंट पहुंचने के लिए निजामुद्दीन पुलिस चौकी के पास लालबत्ती से दाएं मुड़ना होगा। एडवाइजरी में कहा गया है, फिर नीला गुम्बद की ओर सर्विस रोड पर दाएं मुड़ें और लालबत्ती प्वाइंट से मथुरा रोड के मुख्य कैरिजवे जाने के लिए वाहन को नीला गुम्बद की ओर ले जाएं। यातायात पुलिस ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए क्षेत्र में तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी है।

# चाइल्ड केयर संस्थानों को अपग्रेड करेगी दिल्ली सरकार

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार अपने चाइल्ड केयर संस्थानों को अपग्रेड करेगी। महिला और बाल विकास मंत्री आतिशी ने विभाग के अधिकारियों के साथ इस बाबत समीक्षा बैठक की।

बैठक में आतिशी ने कहा कि चाइल्ड केयर संस्थानों में वे बच्चे आते हैं, जो बहुत ही भयावह अतीत से गुजरे होते हैं। ऐसे बच्चों को अपना अतीत भुलाकर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें विशेष देखभाल मिले।

इस दिशा में काम करते हुए दिल्ली सरकार अपने चाइल्ड केयर संस्थानों को अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अंतर्गत बच्चों को स्किल व आर्ट आधारित शिक्षा देने का काम किया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनें और तनाव मुक्त रहें। साथ ही इन संस्थानों के कर्मचारियों को भी एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे

बच्चों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझें और उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चाइल्ड केयर संस्थानों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेगी। उन्हें चाइल्ड केयर संस्थानों में आने वाले बच्चों की जरूरतों को समझने और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद करेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 25 चाइल्ड केयर संस्थान चलाए जा रहे हैं।

# मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा का प्रदर्शन

**नई दिल्ली।** दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सिविल लाइन स्थित आवास इस समय सुर्खियों में है। भाजपा नेता कुलजीत चहल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि सत्ता में आने से पहले वह कहते थे कि उन्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है, वो केवल दो कमरों के फ्लैट में रहेंगे। हालांकि, अब केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर की मरम्मत के नाम पर 44 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस मामले पर भाजपा के नेता विरोध प्रदर्शन कर उनसे जनता के टैक्स के पैसे जवाब मांग रहे हैं। जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में भाजपा नेता इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के आवास के पास पहुंचे। पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारी नेताओं को रोक लिया। इस बीच भाजपा नेताओं ने बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया।

भाजपा नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले खुद को पाक साफ बताते थे। बड़े घर में रहने का विरोध करते थे, अब केजरीवाल मकान की मरम्मत के नाम पर 44 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि जब देश की जनता करोना से परेशान थी, तब केजरीवाल अपने मकान की मरम्मत करा रहे थे। मुख्यमंत्री कहते थे कि वह बड़े घर में नहीं रहेंगे। इसी तरह उनके मंत्री और विधायक भी 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे, लेकिन अब सभी नेताओं को बड़े-बड़े बंगले दिए गए हैं। भाजपा सांसद विजय गोयल ने कहा कि जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करने के मामले में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। अब केजरीवाल का जेल जाने का नंबर है।

# दिल्ली में रोंगटे खड़े करने वाली घटना: 350 मीटर घिसटने से दोनों पैर और पीठ का उधड़ गया था मांस, हड्डियां भी...

**नई दिल्ली।** फिरोजशाह रोड पर अनियंत्रित कार द्वारा ई रिक्शा में टक्कर मारने के बाद चालक को करीब 350 मीटर तक घसीटने के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा है। दुर्घटना के पीड़ित युवक मनोज के शरीर को जिस किसी ने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए।

इतनी दूर घिसटने से मनोज के दोनों पैरों के घुटने से नीचे का पूरा मांस घिस गया था। पीठ से भी मांस हट गया था। इससे पैरों व पीठ की हड्डियां दिखाई देने लगी हैं। नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कच्ची सराय सक्को वाली गली, मुराद नगर गाजियाबाद यूपी निवासी फरमान अपनी बहन, महिला दोस्त व दोस्त के साथ घूमने गुरुग्राम गया था।

सड़क दुर्घटना के समय ये लोग वापस लौट रहे थे। इसने फिरोजशाह रोड पर रिक्शा को पीछे से जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रिक्शा तो आगे चला गया और मनोज हवा में उछलकर कार के बोनट पर जा गिरा। इसके बाद वह नीचे गिरकर पहिए के नीचे फंस गया। इससे कार टेड़ी-मेडी चलने लग गई। लेकिन चालक ने कार रोकने के बजाय उसकी गति बढ़ा दी।

परिणामस्वरूप कार के नीचे फंसा मनोज करीब 350 मीटर तक घिसटता रहा। आगे लाइट सिग्नल व ट्रैफिक होने की वजह से उसे कार रोकनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घिसटने से मनोज के दाहिना पैर के पीछे से और बाएं पैर का आगे की तरफ से व पीठ का मांस पूरी तरह खत्म हो गया।

**कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा**

एक स्कूटर चालक अपने स्कूटर को कार के साथ दौड़ा कर चिल्लाता रहा, मगर कार चालक ने सुनी नहीं। संसद मार्ग थाना पुलिस ने आरोपी फरमान के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी का कहना है कि सड़क दुर्घटना के बाद वह डर गया था और भागने का प्रयास कर रहा था।

**स्विफ्ट कार ने रिक्शे में मारी टक्कर**

नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त प्रणब तायल ने बताया कि यह सड़क दुर्घटना फिरोजशाह रोड पर मंगलवार देर शाम को हुई। हाउसकीपिंग का काम करने वाला मनोज रिक्शे से मंडी हाउस की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने मनोज के रिक्शे में टक्कर मार दी।

**रिक्शा चालक को 350 मीटर तक घसीटा**

चालक फरमान ने कार रोकने की जगह गति बढ़ा दी और मनोज को 350 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कार को रुकवाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मनोज को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस उपायुक्त का कहना है कि मामला दर्ज कर मुरादनगर गाजियाबाद निवासी फरमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस को कार से चखना आदि मिला है। माना जा रहा है कि आरोपी ने शराब पी रखी थी।

## पहलवानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी, नेट बिछाकर सड़क पर की प्रैक्टिस

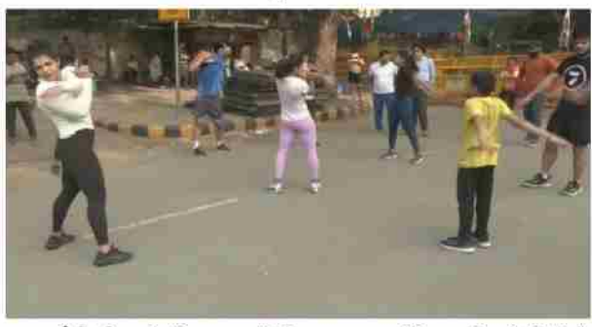

**नई दिल्ली।** ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बीते चार दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच धरने पर बैठे पहलवानों ने आज नेट बिछाकर प्रैक्टिस की और दांवपेंच की जोर आजमाइश की। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों का धरना अभी भी जारी है, लेकिन इस दौरान वो भी सड़क पर कसरत करते नजर आए। उच्चतम न्यायालय ने भी यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग कर रहीं सात महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि बीते दिन ही पहलवानों को समर्थन देने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, सीपीएम नेता वृंदा करात, कांग्रेस नेता उदित राज भी पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मांग की है कि जो पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उस पर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पहलवानों के धरना प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। तीन रात व खुले आसमान के नीचे गुजार चुके हैं। पहलवानों का भी यही कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं है और अब तो पहलवानों ने यहां अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है।

## दिल्ली पुलिस का नया सर्कुलर जारी, लिखा- 'अदालत को मत बताना तुम असली आईओ नहीं हो!'

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक नए सर्कुलर में सब इंस्पेक्टर (एसआई) स्तर के पुलिस अधिकारियों को जांच अधिकारी (आईओ) की अनुपस्थिति में अदालत में पेश होने और अदालत को यह नहीं बताने के लिए कहा गया है कि वे वास्तविक आईओ नहीं थे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदेश में कहा गया- ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां संबंधित आईओ सेवानिवृत्त हो गया है, या अनुपलब्ध है। ऐसे सभी मामलों में, जिस एसआई को केस फाइल सौंपी जाएगी, वह सुनवाई की नियत तारीख पर अदालत में उपस्थित होगा। एसएचओ और इंस्पेक्टर (जांच) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आईओ को मामले के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी दी जाए ताकि वह बदले में अदालत की कार्यवाही से पहले एलडी एएससी/एपीपी को जानकारी दे सके और किसी भी सवाल का जवाब भी दे सके जो सुनवाई के दौरान अदालत उससे पूछना चाहे। आगे लिखा है कि यदि अदालत द्वारा यह रिपोर्ट किया जाता है कि एसआई अदालत को सूचित करता है कि 'वह आईओ नहीं था या मामले से अनजान था', तो डीसीपी उपनिरीक्षक और दो वरिष्ठ निरीक्षकों को निंदा के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के मुताबिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सभी एसएचओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे वास्तविक आईओ की अनुपस्थिति में आईओ के रूप में अदालत के समक्ष मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नया एसआई उपलब्ध कराएं।

# बबिता ने हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया और फिर धोखा दिया : पहलवान का आरोप

**नई दिल्ली।** भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यहां जंतर-मंतर पर धरना दे रहे एक पहलवान ने आरोप लगाया है कि दूसरों की बात क्या करें, हमें हमारी बहन बबिता फोगाट ने ही धोखा दिया है। पहलवान ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, 'बबिता ने हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया। उन्होंने हमसे कहा कि कोई राजनीतिक नेता घटना स्थल पर नहीं आना चाहिए। हमने उनकी हर बात को सुना और सभी नेताओं से कहा कि हमसे मिलने न आएं लेकिन बबिता ने अपने निजी फायदे के लिए सब चीजों का राजनीतिकरण कर दिया। उन्होंने हमारी पीठ पर चाकू मारा और हमें यहां अकेला छोड़ दिया।' उन्होंने कहा, 'न्याय के लिए हमारी लड़ाई में यह सबसे निराशाजनक बात थी लेकिन

हम जानते हैं कि पूरा देश हमारे साथ है और हमारी सच्चाई हमारे साथ है।' इससे पहले दो बार की विश्व चैंपियन विनेश फोगाट ने अपनी चचेरी बहन और भाजपा नेता बबिता की कड़ी आलोचना की। विनेश ने कहा, 'बबिता अपने राजनीतिक करियर को लेकर ज्यादा चिंतित है। उन्हें पहलवानों के हित की कोई चिंता नहीं है।' जनवरी में जब पहलवान पहली बार जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे तब बबिता ने मध्यस्थ की भूमिका निभायी थी। सरकार ने लीजेंड महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की थी जो पहलवानों के आरोपों की जांच करेगी। बबिता को प्रदर्शनकारी पहलवानों के जोर देने पर इस समिति में शामिल किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट पांच अप्रैल को सौंप दी थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समिति ने बृज भूषण को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि पहलवानों के ताजा प्रदर्शन के बाद सरकार को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और मामले को सुलझाने के लिए जल्द फैसला लेना पड़ सकता है।

# दिल्ली सरकार ने पशुओं की बेहतरी के लिए किया पशु कल्याण बोर्ड का गठन- गोपाल राय

**नई दिल्ली।** दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पशुओं की बेहतरी के लिए दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

19 वर्गों में विभाजित कुल 27 सदस्य पशु कल्याण बोर्ड में शामिल किए गए है। यह बोर्ड दिल्ली में पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता की रोकथाम, देखरेख आदि के लिए कार्य करेगी। इसके साथ ही दिल्ली के प्रत्येक जिले में पशु कल्याण कार्यों में शामिल संगठनो को वित्तीय और तकनिकी सहायता भी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ दिल्ली के पहले पशु चिकित्सा कॉलेज के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए है। पशु चिकित्सा कॉलेज का निर्माण दिल्ली के सतबरी में 56 एकड़ में किया जाएगा।

राय ने बताया कि दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों के साथ साथ दिल्ली में रहने वाले पशुओ के कल्याण के लिए कार्य करने में भी हमेशा कृतसंकल्प रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पशुओं की बेहतरी के लिए पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।पशु कल्याण बोर्ड दिल्ली में पशुओ के प्रति क्रूरता की रोकथाम ,देखरेख आदि के लिए कार्य करेगा। साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में पशु कल्याण कार्यों में शमिल संगठनो / निकायों को दिशानिर्देशों सहित वित्तीय

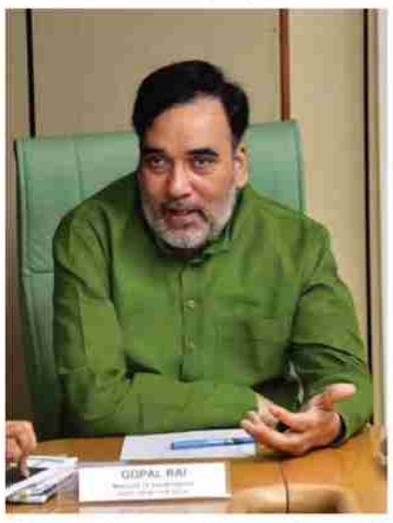

और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। इसके लिए यह बोर्ड शासन निकाय के रूप में कार्यरत रहेगा। 19 वर्गों में विभाजित 27 सदस्यों के इस पशु कल्याण बोर्ड में दिल्ली विधानसभा के विधायक , राज्य में पशु कल्याण कार्यों में सक्रिय रूप से कार्यरत लोग , सम्बंधित विभाग के उच्च अधिकारी ,एसपीसीए ,गौशालाओ और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल किए गए है। उन्होंने बताया कि यह बोर्ड पशु कल्याण से संबंधित कानूनों का दिल्ली में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने और इस कार्य से जुड़ी संस्थाओं की मदद करने का कार्य करेगा।

**दिल्ली के पहले सरकारी पशु चिकित्सा कॉलेज के निर्माण की तैयारियां हुई तेज :**

राय ने आगे बताया कि पशु चिकित्सा विज्ञान आने वाले समय की एक बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यह न केवल मवेशियों और घरेलू जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि जूनोटिक रोगों की जांच और नियंत्रण करके मानव स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है।

दिल्ली में बड़ी संख्या में पालतू जानवर हैं जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सभी प्रकार के जानवरों के बेहतर उपचार के लिए शहर के पहले सरकारी पशु चिकित्सा कॉलेज के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके निर्माण कार्य के पूरे होते ही दिल्ली में भी अपना पहला सरकारी पशु चिकित्सा कॉलेज होगा। आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होने वाले इस कॉलेज का निर्माण दिल्ली के सतबरी में करीबन 56 एकड़ के क्षेत्रफल में किया जाएगा।

# एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर हो : स्वाति मालीवाल

**नई दिल्ली।** दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मांग की है कि महिला रेसलर की यौन शोषण की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। विशेष पुलिस आयुक्त (महिला सुरक्षा) को लिखे पत्र में स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है।

पांच दिन पहले शिकायत किए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। पुलिस अधिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लिखित शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है।

मालीवाल ने कहा कि इस बीच आयोग को महिला रेसलरों की एक और शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच और हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शिकायत करने वाली महिला कोच को और उनके घर वालों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। मालीवाल ने कहा कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज

नहीं की है। यह गंभीर मामला है कि पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

डीसीडब्ल्यू ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कई लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत की है, इनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। इन सभी रेसलर ने बृजभूषण सिंह के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहने के दौरान योग शोषण किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द महिला रिश्वत की शिकायत पर आईपीसी और पोक्सो के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। इसके साथ ही उन अफसरों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।

मालीवाल ने कहा है कि पीड़ित रेसलर ने आयोग को बताया कि 21 अप्रैल को उन्होंने कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। 22 अप्रैल को जब पीड़िता ने फोन कर एसएचओ से एफआईआर दर्ज करने के बारे में जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि अभी शिकायत पर सोमवार के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। एसएचओ ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सोमवार को एफआईआर दर्ज की जाएगी, थाने में शिकायत देने के बाद से ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में तैनात एक आईपीएस की ओर से पीड़ितों के घरवालों को फोन आने लगे हैं और उन्हें परेशान किया जाने लगा है।

*पुलिस अधिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लिखित शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है।*

# दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर थानाध्यक्षों का फेरबदल, 52 थानाध्यक्ष बदले

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस में थानाध्यक्षों का बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। 52 थानाध्यक्ष बदले गए हैं, जिनमें 10 थानों के थानाध्यक्षों को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई ऐसे भी इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले थानाध्यक्ष रह चुके हैं। इससे साफ है कि अब फिर से दिल्ली पुलिस में अनुभवी इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है।

इस बार स्पेशल सेल में तैनात छह इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाने से महकमे में इसको लेकर सबसे अधिक चर्चा है। ऐसा पहली बार हुआ है। पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कार्यभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही ऐसे थानाध्यक्षों के तबादले किए थे, जो एक से अधिक बार थानाध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने अधिकतर थानों में ऐसे इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष नियुक्त किया है, जो पहले कभी थानाध्यक्ष नहीं रहे थे। नियुक्ति से पहले इन इंस्पेक्टरों के साक्षात्कार नहीं लिए गए। इसकी प्रतिकूल असर यह पड़ा था कि छह माह बाद ही बड़ी संख्या में कई थानाध्यक्षों ने मुख्यालय में पेश होकर थानाध्यक्ष पद से हटाने के लिए आवेदन किया। वर्तमान पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के कार्यकाल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में थानाध्यक्षों के तबादले किए गए हैं। नियुक्ति के लिए मुख्यालय में पिछले सितंबर से इंस्पेक्टरों के साक्षात्कार लेने का सिलसिला शुरू किया गया। पहले 1994-1995 बैच फिर 1996-1997 बैच के इंस्पेक्टरों के साक्षात्कार लिए गए। साक्षात्कार की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि पास होने के बावजूद थानाध्यक्ष न नियुक्त होने पर वह पुलिस आयुक्त के पास अपील कर सके। विशेष आयुक्त एचआर आरएस कृष्णैया को चयन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लंबे समय तक साक्षात्कार चलने और थानाध्यक्षों की लिस्ट आने में देरी होने पर महकमे में तरह-तरह की चर्चा होती रही।

## सीएम बीरेन सिंह के दौरे से पहले भीड़ ने कार्यक्रम स्थल को फूंका, क्षेत्र में तनाव

इंफाल, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दौरे से एक दिन पहले भीड़ ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब नौ बजे अनियंत्रित भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भीड़ को तितर-बितर कर दिया, लेकिन आगजनी की घटना से कार्यक्रम स्थल को नुकसान पहुंचा है।

यह घटना राज्य की राजधानी इंफाल से करीब 63 किलोमीटर दूर न्यू लमका में हुई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो गई है। पुलिस ने जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने कहा कि गुस्साई भीड़ ने न्यू लमका के पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नए स्थापित ओपन जिम को आंशिक रूप से आग के हवाले कर दिया, जिसका उद्घाटन बीरेन सिंह शुक्रवार दोपहर में करने वाले हैं।

सीएम बीरेन सिंह जिम के अलावा खेल सुविधा का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही उनका एक अन्य समारोह में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है या नहीं।

दरअसल, स्वदेशी जनजाति नेताओं के मंच ने सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक पूरा चुराचांदपुर बंद का आह्वान किया था, इसी बीच भीड़ उग्र हो गई और सीएम के कार्यक्रम स्थल पर हमला कर दिया। जनजाति नेताओं के मंच ने दावा किया कि किसानों और अन्य आदिवासी निवासियों के आरक्षित वन क्षेत्रों को खाली करने के लिए चल रहे बेदखली अभियान का विरोध करते हुए बार-बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद सरकार ने लोगों की दुर्दशा को दूर करने की इच्छा या ईमानदारी का कोई संकेत नहीं दिखाया है।

## जोधपुर में पाक विस्थापित हिन्दुओं के घरों पर चला बुलडोजर

जयपुर, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। पाकिस्तान के हिन्दू प्रवासियों के कच्चे-पक्के घरों पर राजस्थान सरकार का बुलडोजर चला।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा पाकिस्तान के हिन्दू प्रवासियों के 70 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। विस्थापितों ने कहा, 'हमें पाकिस्तान से भी निकाला गया और अब यहां भी हमारे घर तोड़े गए।'

जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बताया कि यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। काम को लेकर पहले ही पब्लिक नोटिस जारी किया जा चुका है।

यहां यह बताना जरूरी है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के चौका गांव से अतिक्रमण हटवाया। प्राधिकरण ने राजीव नगर कॉलोनी के बी और सी सेक्टर की करीब 400 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

अभियान के दौरान, पाकिस्तान के हिन्दुओं का दर्द काफी गहरा था। अपने घरों को उजड़ा हुआ देख महिलाएं और बच्चे रोने लगे।

जेडीए ने कहा, जिस स्थान पर ये घर बनाए गए थे वह राजीव गांधी आवास योजना खसरा नंबर 61 है और कार्रवाई हिन्दुओं पर नहीं बल्कि अतिक्रमण पर की गई है।

इस बीच पाकिस्तान के हिन्दू प्रवासियों ने इस कार्रवाई को लेकर जोधपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस जमीन पर जेडीए ने कार्रवाई की है वह ग्राम पंचायत की है।

अप्रवासियों में से एक ने कहा, हमने जमीन के लिए 70,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक दिए हैं, हालांकि, ऐसा लगता है कि भू-माफिया ने हमें धोखा दिया है।

## 'मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के आधार को किया खत्म', राजनाथ की शांगफू को दो टूक

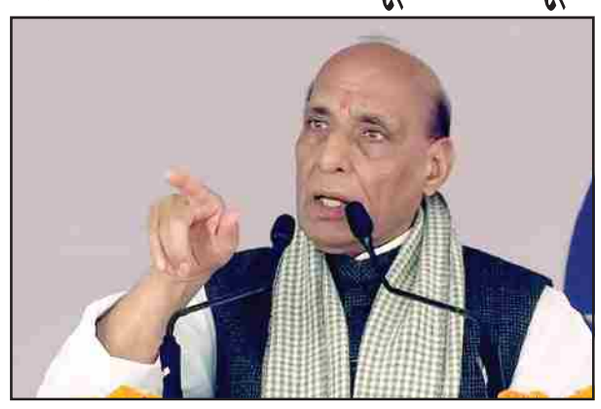

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष ली शांगफू के साथ वार्ता की। नई दिल्ली में हुई यह बैठक एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत-चीन संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति पर निर्भर करता है। एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की जरूरत है। दोनों देशों के संबंध तभी मजबूत हो सकते हैं, जब सीमा पर शांति हो और एक-दूसरे की संपभूता का सम्मान किया जाए।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद पर चर्चा हुई। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शांगफू के दिल्ली पहुंचने के बाद यह बैठक हुई। भारत एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। तीन साल पहले पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद यह चीन के रक्षा मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। कुछ दिन पहले ही सीमा विवाद को खत्म करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं ने 18वें दौर की सैन्य वार्ता की थी।

रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह-ली शांगफू की वार्ता के संबंध में कहा कि दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के घटनाक्रम के बारे में खुलकर बातचीत की। राजनाथ सिंह ने शांगफू से कहा कि चीन-भारत संबंधों का विकास सीमा पर अमन-चैन पर आधारित है। मौजूदा समझौतों के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण बुनियाद को नुकसान पहुंचा। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सुलझाने की जरूरत है।

23 अप्रैल को हुई कोर कमांडर वार्ता में दोनों पक्ष संपर्क बनाए रखने और पूर्वी लद्दाख में बचे अनसुलझे मुद्दों पर जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमत हुए थे। हालांकि, विवाद खत्म करने के लिए आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला था। भारत का स्पष्ट रुख है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

गोवा में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीनी विदेश मंत्री छिन कांग भी अगले सप्ताह भारत आने वाले हैं। बैठक चार और पांच मई को होनी है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कजाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता की। पाकिस्तान को छोड़कर चीन, रूस और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के रक्षा मंत्री दिल्ली में हो रही बैठक में भाग ले रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऑनलाइन माध्यम से बैठक में हिस्सा लेंगे।

इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद ने भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत सैन्य संबंधों को और सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि जनरल अहमद और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दोनों सेनाओं के बीच संपूर्ण सहयोग की समीक्षा की और संबंधों को और विस्तार देने के तरीके खोजने पर विचार किया।

भारत यात्रा पर आए बांग्लादेश के जनरल ने नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह से भी मुलाकात की।

जनरल अहमद ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से बुधवार को मुलाकात की थी। वह तीन दिवसीय भारत यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे थे।

## शहीदों को सीएम बघेल ने दी श्रद्धांजलि, कहा- नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई तेज की जाएगी

दंतेवाड़ा, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हुए सुरक्षाबल के 10 जवानों और वाहन चालक को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि के दौरान शहीद पुलिस जवानों और वाहन चालक के रोते-बिलखते परिजनों ने भारत माता की जय के नारे के साथ शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।

शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद बघेल ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तथा नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा।

नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में बुधवार को नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के काफिले में शामिल एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में जिला रिजर्व गार्ड के दस जवान और एक वाहन चालक की मृत्यु हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन करली में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।

पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, सांसद दीपक बैज, फूलोदेवी नेताम तथ अन्य नेताओं ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया।

इस दौरान बघेल ने वहां मौजूद शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया।

श्रद्धांजलि के बाद मुख्यमंत्रील ने एक शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। जवानों के पार्थिव शरीर को शव वाहन से उनके निवास स्थान के लिए भेजा जा रहा है जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

पुलिस लाइन में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी तथा नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई और तेज की जाएगी।

बघेल ने कहा, ''हमारे जवान नक्सलियों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले चार साल में नक्सलियों के कोर एरिया में 75 कैंप लगाए गए हैं जबकि पहले के कैंप बफर एरिया में लगाए गए थे। अब जगरगुंडा (सुकमा जिला) जाने के लिए सुकमा (जिला मुख्यालय) जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अरनपुर (दंतेवाड़ा) और भैरमगढ़ (बीजापुर) से वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें बन चुकी हैं। पुवर्ती (बीजापुर जिले में) जिसे हिडमा (खूंखार माओवादी कमांडर) का मुख्यालय कहा जाता है, को चारों तरफ से (सुरक्षा बलों के शिविरों द्वारा) घेर लिया गया है।''

उन्होंने कहा, ''बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं और पुलिस शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। नक्सलियों को बैकफुट पर धकेल दिया गया है और ऐसा हमला दो साल के अंतराल के बाद हुआ है, जिसे नक्सलियों ने निराशा में अंजाम दिया है।''

माओवादी गतिविधियों को रोकने के सरकारी दावों के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा, ''पहले जवानों पर उनके शिविरों में हमले किए गए थे, लेकिन अब जंगल में तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही है। अब हमारे जवान शिविर में जान नहीं गंवाते।''

उन्होंने कहा कि नक्सली गर्मियों के दौरान हमला करते हैं जब जंगल में दूर तक देखा जा सकता है, क्योंकि पत्तियां और घास सूख जाती हैं।

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और अन्य नेताओं ने भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी।

इस दौरान शहीद पुलिस जवानों के परिवार की महिलाएं और बच्चे रो रहे थे जिन्हें महिला सुरक्षाकर्मी सांत्वना देने का प्रयास कर रही थीं।

## मुक्केबाज कौर सिंह का निधन, मान ने जताया शोक

चंडीगढ़, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज कौर सिंह का कुरूक्षेत्र के एक अस्पताल में बृहस्पतिवार को निधन हो गया।

वह 74 वर्ष के थे और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे ।

उन्होंने जनवरी 1980 में एक नुमाइशी मैच में महान मुक्केबाज मुहम्मद अली का सामना किया था । उन्होंने दिल्ली में 1982 एशियाई खेलों में हैवीवेट मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था ।

कौर को 1982 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से नवाजा गया था ।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार , पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व ओलंपियन और अनुभवी मुक्केबाज कौर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है ।

इससे पहले पंजाब सरकार ने इस महीने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में पंजाब के चार महान खिलाड़ियों की जीवनी शामिल करने की घोषणा की थी जिनमें महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर, एथलीट मिल्खा सिंह, ओलंपियन गुरबचन सिंह रंधावा और कौर सिंह शामिल हैं ।

## समलैंगिक विवाह का मामला संसद पर छोड़ दें

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (एजेन्सी)। केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह समलैंगिक विवाहों को कानूनी मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिकाओं में उठाए गए प्रश्नों को संसद के लिए छोड़ने पर विचार करे।

केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि शीर्ष न्यायालय एक बहुत ही जटिल मुद्दे से निपट रहा है, जो एक गहरा सामाजिक प्रभाव रखता है।

मेहता ने कहा, मूल प्रश्न यह है कि इस बारे में फैसला कौन करेगा कि विवाह किनके बीच है। उन्होंने न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति एसआर भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से कहा कि कई अन्य विधानों पर भी इसका अनपेक्षित प्रभाव पड़ेगा, जिस पर समाज में और विभिन्न राज्य विधानमंडलों में चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। शीर्ष न्यायालय में विषय की सुनवाई जारी है। विषय की सुनवाई के प्रथम दिन, 18 अप्रैल को केंद्र ने शीर्ष न्यायालय से कहा था कि उसकी प्राथमिक आपत्ति यह है कि क्या न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर सकता है या इस पर पहले संसद को विचार करना जरूरी है। मेहता ने कहा था कि शीर्ष न्यायालय जिस विषय से निपट रहा है वह वस्तुत: विवाह के सामाजिक-विधिक संबंध से संबंधित है, जो सक्षम विधायिका के दायरे में होगा।

उन्होंने कहा था, यह विषय समवर्ती सूची में है, ऐसे में हम इस पर एक राज्य के सहमत होने, एक अन्य राज्य द्वारा इसके पक्ष में कानून बनाने, एक अन्य राज्य द्वारा इसके खिलाफ कानून बनाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते इसलिए राज्यों की अनुपस्थिति में याचिकाएं विचारणीय नहीं होंगी। यह मेरी प्राथमिक आपत्तियों में से एक है।

पीठ ने 18 अप्रैल को स्पष्ट कर दिया था कि वह इन याचिकाओं पर फैसला करते समय विवाह से जुड़े पर्सनल लॉ पर विचार नहीं करेगा। केंद्र ने शीर्ष न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामों में एक में याचिकाओं को सामाजिक स्वीकार्यता के उद्देश्य के लिए एक शहरी संभ्रांतवादी विचार का प्रतिउबब बताया था।

### सी20 इंडिया 2023 वर्किंग ग्रुप के सम्मेलन के लिए तैयारी पूरी

## सम्मेलन से लोगों को सिक्किम के बारे में जानने का मिलेगा अवसर : डॉ. मनीषा सुधीर

**अनुगामिनी का.सं.**

गंगटोक, 27 अप्रैल । सिक्किम सरकार के सहयोग से अमृता विश्वविद्यालय केरल द्वारा सतत एवं लचीले जलवायु, पर्यावरण समुदायों एवं शुद्ध शून्य लक्ष्यों पर सी20 इंडिया 2023 वर्किंग ग्रुप का सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट कम्युनिटीज कॉन्क्लेव 29 और 30 तारीख को राजधानी गंगटोक में आयोजित होने जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भूमि राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के सह आयोजन में होने वाले इस कॉन्क्लेव की पूरी तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में 22 देशों के 200 प्रतिनिधियों के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से दुनिया भर से कई अन्य प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है।

आज यहां इस संबंध में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में सी20 इंडिया वर्किंग ग्रुप की समन्वयक एवं अमृता विश्वविद्यालय की प्रोवोस्ट डॉ. मनीषा सुधीर और राज्य भूमि राजस्व व आपदा प्रबंधन सचिव अनिल राज राई ने इस सम्बंध में जानकारी दी। इस अवसर पर एलआरडीएम अतिरिक्त सचिव राजीव रोका और अमृता विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक जीसी खनाल भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर सी20 समन्वयक डॉ. मनीषा सुधीर ने कहा कि सी20 इंडिया 2023 जी20 के आधिकारिक समूहों में से एक है जो दुनिया भर के नागरिक सामाजिक संगठनों को लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देने का एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सी20 कॉन्क्लेव भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सतत एवं लचीले समुदायों से सम्बंधित मौजूदा वैश्विक नीतियों की समझ हेतु पूरे विश्व के नागरिक सामाजिक संगठनों, नीति निर्माताओं, सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों के साथ व्यापक संवाद और जुड़ाव लाना है। इनके समाधानों को सितंबर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन में देशों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

वहीं, डॉ. सुधीर ने सिक्किम में आयोजित होने वाले सम्मेलन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोगों को यह देखने का अवसर मिलेगा कि सिक्किम ने कैसे सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए जलवायु लचीलापन और आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव दुनिया भर के सीएसओ को सिक्किम आने और जलवायु लचीलापन और सामाजिक न्याय, पर्यावरण स्थिरता, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा। इस दौरान एलआरडीएम सचिव अनिल राज राई ने राज्य में सी20 कॉन्क्लेव की मेजबानी हेतु मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और गंगटोक में इसके आयोजन के लिए अमृता विश्वविद्यालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे बताया कि कॉन्क्लेव में चिंतन भवन में पूर्ण सत्र के समानांतर एनबी भंडारी डिग्री कॉलेज तादोंग और जनता भवन डीपीएच में सतत विकास और जलवायु लचीलापन एवं ऊर्जा स्थिरता तथा शुद्ध शून्य लक्ष्यों पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूल-कॉलेजों के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर भाग लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 29 अप्रैल को कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस अवसर पर युगांडा के राजदूत जॉयस किकाफुंडा, राज्य के भूमि राजस्व मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा एवं जी20 प्रधान समन्वयक विजय नांबियार भी समारोह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में अमृता विश्व विद्यापीठम पुरी के अध्यक्ष स्वामी अमृतस्वरूपानंद पुरी और सी20 के सदस्य ट्रोइका भी मौजूद रहेंगे। इसके अगले दिन 30 अप्रैल को कार्यक्रम के समापन समारोह में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अपना सम्बोधन रखेंगे। इसके अलावा समापन समारोह में भारत में गाम्बिया के राजदूत मुस्तफा जवारा और मणिपुर सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थोंगम बिस्वजीत सिंह भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके अलावा इसमें जी20 देशों के कई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति भी शामिल होंगे।


डियर साप्ताहिक लॉटरी
हावड़ा निवासी ने
₹ 1 करोड़ जीते

हावड़ा, पश्चिम बंगाल के श्री माईदुल मल्लिक ने **20.02.2023** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नम्बर **45E 97967** है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज़ क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। "मैंने एक करोड़पति बनने के बारे में कल्पना भी नहीं की थी। डियर लॉटरी ने मेरे द्वारा महज कुछ रुपए की खरीदी गई टिकट के साथ मुझे एक करोड़पति बना दिया है। इस आश्चर्यजनक अवसर के लिये मैं डियर लॉटरी तथा नागालैंड स्टेट लॉटरीज को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।" विजेता ने कहा। डियर लॉटरी के ड्रॉ लाइव दिखाये जाते हैं।


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्टो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com